mediaauditornews@gmail.com mediaauditor Epaperdainikmediaauditor.in mediaauditor वर्ष-29 अंक-123 | पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

रीवा

06 मई 2025 मंगलवार

दैनिक मीडियाऑडीटर

रीवा, सतना से एक साथ प्रकाशित

पूर्व चयनकर्ता प्रसाद ...

@ पेज 7

अमरनाथ यात्रा से 2 महीने पहले सामने आई बाबा बर्फानी की तस्वीरें

अयोध्या (एजेंसी)। बाबा बर्फानी के भक्त हमेशा ही भोलेनाथ के खास दर्शन के लिए आतुर रहते हैं। आधिकारिक तौर पर अमरनाथ यात्रा के शुरू होने में अभी 2 महीने का समय बाकी है, लेकिन कुछ भक्त पहले ही पवित्र गुफा तक जाने में कामयाब हो चुके हैं

- **कुछ भक्त पहले ही पवित्र गुफा तक जाने में कामयाब हुये**

और यह फोटो उन्होंने ही गुफा पर लिए हैं। पंजाब के रहने वाले यह भक्त कुछ दिन पहले गुफा के दर्शन के लिए गए थे। हालांकि, आधिकारिक तौर अभी तक कोई भी श्राइन बोर्ड का अधिकारी या सुरक्षा कर्मी तक गुफा नहीं पहुंच सके हैं।

इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां शुरू हो

गयी है और यात्रा के रास्ते पर बर्फ को साफ करने का काम शुरू किया गया है। बर्फ को काट कर ट्रैक को यात्रियों के चलने लायक बनाने का काम दोनों रास्तों (बालतल और चंदनवाड़ी) से शुरू किया गया है, ताकि यात्रा के लिए तय समय से पहले ट्रैक बनाने का काम पूरा किया जा सके। हालांकि, पूरे रस्ते पर भारी बर्फबारी के चलते इस काम में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने की तैयारियों की समीक्षा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को श्रीनगर के पंथा चौक में अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट कैंप पर जाकर यात्रा के लिए होने वाली तैयारियों की समीक्षा की। पहलगाम हमले के बाद भी अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तो के उत्साह में कोई भी फर्क नहीं आया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 3 लाख 60 हजार से ज्यादा लोग अब तक यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं और इस में और ज्यादा बढ़ोतरी होने की भी उम्मीद है।

3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा: ट्रैक पर इस बार पिछले सालो के मुकाबले कई गुना ज्यादा बर्फ बारी हुई है और अभी भी पूरे रास्ते पर दस से बीस फीट बर्फ मौजूद है। इसका सबूत इन तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है। यह तस्वीरें पंजतरणी और शेषनाग में ली गई हैं। इस साल की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और 19 अगस्त को रक्षा बंधन दिन समाप्त होगी।

संक्षिप्त समाचार

भारत-पाकिस्तान को युद्ध से बचना चाहिए

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पिछले कई सालों में सबसे ज़्यादा है। दोनों देशों के बीच बनी युद्ध की स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने कहा है कि, मैं दोनों देशों की सरकारों और लोगों का बहुत सम्मान करता हूं और उनके प्रति बहुत आभारी हूं, इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के काम में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भी, खासकर संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के लिए। और इसलिए मुझे यह देखकर दुख होता है कि दोनों देशों के रिश्ते इतने ख़राब हो गए हैं। गुटारेस ने कहा कि मैं 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले के बाद की भावनाओं को

समझता हूं। मैं एक बार फिर उस हमले की कड़ी निंदा करता हूँ और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। नागरिकों को निशाना बनाना हर हाल में अस्वीकार्य है, और ज़िम्मेदार लोगों को विश्वसनीय, वैध तरीकों से न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। लेकिन इस बीच दोनों देशों को सैन्य टकराव से बचना भी ज़रूरी है, जो आसानी से नियंत्रण से बाहर हो सकता है, ख़ास तौर पर इस महत्वपूर्ण समय में। उन्होंने कहा कि अब अधिकतम संयम और युद्ध की कगार से पीछे हटने का समय है। दोनों देशों के साथ अपने निरंतर संपर्क में यही मेरा संदेश रहा है। कोई गलती न करें, सैन्य समाधान कोई समाधान नहीं है, और मैं शांति की सेवा में दोनों सरकारों को अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कहा, ÷संयुक्त राष्ट्र किसी भी ऐसी पहल का समर्थन करने के लिए तैयार है जो तनाव कम करने की कूटनीति और शांति के लिए नई प्रतिबद्धता को बढ़ावा दे।

चीन पाकिस्तान के समर्थन में अलापा शांति का राग,

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर इस्लामाबाद और दिल्ली के बीच तनाव के बीच सोमवार को चीनी राजदूत जियांग जैदोंग ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली

जरदारी से मुलाकात की। चीनी राजदूत ने कहा कि चीन दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान का हमेशा समर्थन करेगा। सरकारी 'रेडियो पाकिस्तान' की रिपोर्ट के मुताबिक, जैदोंग ने राष्ट्रपति जरदारी से मुलाकात की और पाकिस्तान एवं भारत के बीच तनाव सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान राष्ट्रपति जरदारी ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत की ओर से हाल में उठाए गए कदमों पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इस तरह की कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध और खराब हो गए हैं। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। रेडियो पाकिस्तान' की रिपोर्ट के अनुसार, चीनी राजदूत ने चीन और पाकिस्तान के बीच रिश्ते को मजबूत बताया, जिन्होंने चुनौतीपूर्ण समय में हमेशा एक-दूसरे का समर्थन किया है। जियांग जैदोंग ने पाकिस्तान का दृष्टिकोण साझा करने के लिए राष्ट्रपति जरदारी को धन्यवाद दिया और इस बात पर जोर दिया कि ÷दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने की दोनों देशों की साझा इच्छा को पूरा करने के लिए चीन हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करेगा।÷ चीनी राजदूत ने बीते सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की थी।

पेट्रोल पंप पर डिजिटल पेमेंट नहीं स्वीकार किए जाएंगे

नागपुर (एजेंसी)। महाराष्ट्र के नागपुर में 10 मई से पेट्रोल पंप पर डिजिटल पेमेंट नहीं स्वीकार किए जाएंगे। विदर्भ पेट्रोलियम डीलर असोसिएशन ने यह फैसला किया है। नेशनल सायबर क्राईम पोर्टल ने एक पेट्रोल पंप मालिक का खाता ब्लॉक कर दिया है। इसके बाद यह फैसला किया गया है। पेट्रोल पंप मालिक के बैंक खाते में साइबर क्रिमिनल ने फ्रॉड ट्रांजेक्शन किए थे। इसी वजह से उनका अकाउंट ब्लॉक किया गया है। अकाउंट ब्लॉक होने के बाद मालिक ने ऑनलाइन पेमेंट नहीं स्वीकार करने का फैसला किया है। आज के समय में पूरे देश में डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से नागरिक तेजी से डिजिटल माध्यम से लेन-देन करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस बीच नागपुर में विदर्भ पेट्रोलियम डीलर असोसिएशन के फैसले के चलते नागपुर में नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।0 मई से नागपुर के पेट्रोल पंप पर डिजिटल पेमेंट नहीं होगा। आप को अगर अपने वाहन में पेट्रोल डलवाना है तो जेब में कैश लेकर पेट्रोल पंप जाना होगा। विदर्भ पेट्रोल पंप डीलर असोसिएशन के अध्यक्ष अमित गुप्ता ने बताया ÷नेशनल सायबर क्राईम पोर्टल से पेट्रोल पंप मालिक के बैंक खाते में सायबर क्रिमिनल ने फ्रॉड ट्रांजेक्शन किए, जिस वजह से उनके अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं। कुछ के बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं। अकाऊंट मे लिन मार्क लगे हैं। इसलिए हमने यह फैसला किया है कि हम नागपुर के पेट्रोल पंप पर डिजिटल पेमेंट 10 मई से स्वीकार नहीं करेंगे।÷

भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव जारी

सात मई को देश में बजेंगे सायरन, केन्द्र ने मॉक ड्रिल का दिया निर्देश

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। एक तरफ तो पाकिस्तान में संसद की बैठक चल रही है तो वहीं, दूसरी तरफ भारत में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार 5 अप्रैल 2025 को बड़ा कदम उठाते हुए देश के कई राज्यों को नागरिकों की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया कि राज्य 7 मई 2025 को प्रभावी तरीके से नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन करेंगे ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

इस दौरान निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। जैसे- 1. हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन। 2. शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों, छात्रों आदि को प्रशिक्षण। 3. क्रैश ब्लैक आउट उपायों का प्रावधान। 4. महत्वपूर्ण संयंत्रों/प्रतिष्ठानों को समय से पहले छिपाने का प्रावधान। 5. निकासी योजना का अद्यतनीकरण और उसका पूर्वाभ्यास

1971 में भी दिखा था ऐसा ही मंजर: केंद्र सरकार के आदेश का समय बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार ऐसा अभ्यास 1971 में किया गया था, जिस साल भारत और पाकिस्तान के बीच दो मोर्चों पर युद्ध हुआ था। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद, जिसमें पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों ने 26 नागरिकों की हत्या कर दी थी। उसके बाद दोनों देशों की कश्मीर से लगती सीमा पर तनाव कम होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान ने लगातार 11 रातों से नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की है। भारत ने इस्लामाबाद की बार-बार सीमा पार से की गई गोलीबारी का कड़ा जवाब दिया है।

फिरोजपुर के छावनी क्षेत्र में लाइटें बंद की गई: पंजाब के फिरोजपुर में कल रात 9 से 9-30 बजे तक छावनी क्षेत्र में लाइटें बंद कर दी गई थीं। पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के एक अधिकारी से अभ्यास के निर्धारित समय पर बिजली काटने को कहा। छावनी बोर्ड के अधिकारी ने एक पत्र में कहा, ÷आपसे अनुरोध है कि इस अवधि के दौरान पूर्ण ब्लैकआउट को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें।

दुल्हन की विदाई से पहले ही भाइयों की उठी अर्थी

हाजीपुर (एजेंसी)। बिहार के हाजीपुर में रफ्तार के कहर ने एक शादी समारोह को मातम में बदल दिया। एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन युवकों की जान चली गई। यह दुखद घटना हाजीपुर के चांदपुर गांव

की है, जहां शादी के जश्न में डूबे परिवार के बेटे के साथ उसके चचेरे भाई और दोस्त तीनों काल के गाल में समा गए। दरअसल, दुल्हन का भाई सोनू कुमार (20), अपने चचेरे भाई 19 वर्षीय रंजन कुमार (जो लाल मोहन पासवान का पुत्र था), और एक दोस्त 18 वर्षीय राजीव कुमार (जो अवधेश पासवान का पुत्र था) के साथ बीती रात घर से दही खरीदने के लिए निकले थे। बताया जा रहा है कि वे पूजा देखने भी जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। आज उस घर में खुशियों की शहनाई बजनी थी, बहन की डोली उठनी थी, लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। बहन की शादी से पहले ही तीनों भाइयों की अर्थी उठ गई, जिससे पूरे परिवार में कोहराम मच गया।

साइबर अटैक अलर्ट, पाकिस्तानी साइबर फोर्स का दावा

भारतीय रक्षा संस्थानों में लगाई सेंध

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसा माहौल बन चुका है। दोनों देश हर मोर्चे पर एक-दूसरे को पटखनी देने की कोशिश कर रहे हैं। साइबर अटैक भी इसमें शामिल हैं। इस बीच पाकिस्तान साइबर फोर्स नाम के एक अकाउंट ने दावा किया है कि उसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ी वेबसाइट को हैक कर लिया है और अहम डेटा चुरा लिया है। पाकिस्तान साइबर फोर्स नाम के एक्स अकाउंट के जरिए खुलासा किया गया है कि इस समूह ने कथित तौर पर भारतीय सैन्य इंजीनियरिंग सेवा और मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान से अहम डेटा हासिल कर लिया है।

सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान साइबर फोर्स का दावा इस बात का प्रतीक है कि लॉगिन क्रेडेंशियल सहित रक्षा कर्मियों से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी भी साइबर अटैकर्स के पास हो सकती है। यह भी बताया गया है कि साइबर अटैकर्स ने रक्षा मंत्रालय के तहत एक पीएसयू कंपनी आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट को भी खराब करने का प्रयास किया। वेबसाइट को पाकिस्तान के झंडे और अल खालिद टैंक का उपयोग करके खराब किया गया है।

सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी एएनआई ने यह भी

बताया है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियात के रूप में आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की वेबसाइट को जानबूझकर पूरी तरह से ऑफलाइन कर दिया गया है। इस दौरान वेबसाइट को ऑडिट किया जाएगा और यह पता करने की कोशिश की जाएगी कि साइबर अटैक से वेबसाइट को कितना नुकसान हुआ है और ऐसे हमलों को भविष्य में कैसे रोका जा सकता है। इसके अलावा, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और एजेंसियां ??किसी भी अतिरिक्त साइबर हमले का पता लगाने के लिए साइबरस्पेस की सक्रिय रूप से निगरानी कर रही हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान से जुड़े साइबर अटैकर्स के अटैक को पहचानने की कोशिशें की जा रही हैं।

दिल्ली में आंधी-तूफान के साथ बारिश के आसार

मौसम विभाग का अलर्ट जारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों मौसम सुहाना है। रुक-रुककर हो रही बारिश और बादलों की आवाजाही ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से 0.5 डिग्री कम है। दिल्ली में सुबह 8-30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 75 प्रतिशत दर्ज की गई।

मौसम विभाग ने दिन में आंधी-तूफान के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। शुक्रवार को दिल्ली में मई के महीने में सर्वाधिक बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (ढ्ढरूष्ठ) के अनुसार, सफदरजंग मौसम केंद्र ने देर रात 2-30 बजे से सुबह 8-30 बजे तक मात्र छह घंटों में 77 मिमी बारिश दर्ज की थी। वर्ष 1901 से जब से रिकॉर्ड रखना शुरू हुआ है तब से मई महीने में यह दिल्ली में 24 घंटे के भीतर हुई दूसरी सबसे अधिक वर्षा थी।

वहीं, दिल्ली में सुबह 9.00 बजे वायु

गुणवत्ता सूचकांक 212 दर्ज किया गया जो 'खराब' श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, शून्य से 50 के बीच, त्तद्ब को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को 'मध्यम', 201 से 300 के बीच को 'खराब', 301 से 400 के बीच को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है।

उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में लगी भीषण आग

1 किलोमीटर दूर तक दिखाई दी लपटें

उज्जैन (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। मंदिर के शंख द्वार के ऊपर सोमवार दोपहर भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुंआ लगभग एक किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रहा था, जिससे आस-पास के इलाके में हड़कंप मच गया।

आग लगने की जानकारी लगते ही महाकाल मंदिर समिति के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। जानकारी मिलते ही दमकल की चार गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए गए। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। करीब 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग मंदिर के सीसीटीवी कंट्रोल रूम के ऊपर रखी बैटरी में लगी थी।

आग के कारण कुछ देर के लिए दर्शन व्यवस्था रोक दी गई। जब आग पर काबू पा लिया गया, उसके बाद दर्शन फिर से शुरू हुए। आग से किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है ना ही कोई हताहत हुआ है। घटना की जानकारी लगते ही कलेक्टर रोशन कुमार, एसपी प्रदीप शर्मा, महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक सहित नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि यह आग कंट्रोल रूम के ऊपर लगी है। यहां प्रदूषण बोर्ड का एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ था, जलकर खाक हो गया है। यहां कई बैटरियां रखी थीं, जिनमें आग लगी है। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

भारत-पाक सीमा पर गिरफ्तार हुआ संदिग्ध शख्स

नई दिल्ली (एजेंसी)। पंजाब के गुरदासपुर में कल रात एक पाकिस्तानी व्यक्ति को अवैध रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया, इस संदिग्ध शख्स की उम्र 24 वर्ष है और इसे पंजाब पुलिस ने

गिरफ्तार किया है। इस घुसपैठिए की पहचान हुसनैन के रूप में हुई है। उसके पास पाकिस्तान का राष्ट्रीय पहचान पत्र था। पुलिस को हुसनैन के पास से 40 रुपये की पाकिस्तानी मुद्रा मिली। वह अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास भटक रहा था। अभी तक की पूछताछ में पुलिस को किसी आतंकी लिंक का पता नहीं चला है। 03 मई 2025 को लगभग रात्रि के 11.10 बजे, सीटी संदीप घोष, बीओपी साहापुर फॉरवर्ड (दरिया मंसूर की एक फ़्लैंकिंग बीओपी) के एओआर में पीटीजेड कंट्रोल रूम में हिट पॉइंट नंबर 01 पर ड्यूटी करते हुए, बीपी नंबर 63/एम की सीमारेख में, बीएस बाड़ से आगे और भारतीय क्षेत्र के लगभग 250 मीटर अंदर, फल्कू नाला के पास संदिग्ध गतिविधि देखी। एक अज्ञात व्यक्ति, जिसे बाद में एक पाकिस्तानी नागरिक के रूप में पहचाना गया। वह शख्स झाड़ियों में छिपा हुआ था। सीटी घोष ने तुरंत कोर कमांडर को सतर्क किया, जो तुरंत ही क्यूआरटी और पूरी टीम के साथ उस स्थान पर पहुंचे। इलाके की घेराबंदी की गई और संदिग्ध को बीओपी दरिया मंसूर के जवानों ने लगभग 2345 बजे बीएस बाड़ और आईबी के बीच सफलतापूर्वक पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति को 03 मई 2025 को लगभग 23.50 बजे प्रारंभिक पूछताछ के लिए बीओपी दरिया मंसूर लाया गया।

संगीत का मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान : राज्यपाल

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि संगीत हमेशा ही मन को भाता है। मनुष्य की हर उम्र में संगीत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्यपाल श्री पटेल ने रविवार को राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर के छठवें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता कबीर लोक भजन गायक पद्मश्री कालूरामबामनिया ने की। इस मौके पर वरिष्ठ तबला वादक एवं शिक्षाविद् प्रो. किरण देशपाण्डे विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय भारतीय संगीत को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। महाविद्यालय के अनेकों छात्रों ने संगीत के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में युवाओं को अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान देना चाहिए। संगीत विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के बाद जिन छात्रों को पुरस्कृत किया गया है वे अपने जीवन में संगीत के माध्यम से देश विकास में अपना सहयोग करें। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि वरिष्ठ तबला वादक प्रो. किरण देशपाण्डे के जीवन से युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए।

वे जिस प्रकार से 87 वर्ष की उम्र में भी तबला वादन कर रहे हैं, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार क्रिकेट में खिलाड़ी शतक लगाते हैं, उसी प्रकार प्रो. देशपाण्डे भी अपनी उम्र का शतक लगाएँ, यह हम सबकी कामना है। दीक्षांत समारोह में वरिष्ठ तबला वादक एवं शिक्षाविद् प्रो. पं. किरण देशपाण्डे ने कहा कि उनका तबला वादन विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट उपाधि से सम्मानित किए जाने के प्रति धन्यवाद ज्ञापन हैं। समारोह में कबीर लोक भजन गायक पद्मश्री कालूराम बामनिया ने जीवन में गुरू की महत्ता पर भजन की प्रस्तुतियां दी। दीक्षांत समारोह में संगीत विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने सहरिया जनजाति नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति दी। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल को कार्यक्रम के प्रारंभ में शोभा यात्रा निकालकर मंच तक लाया गया।

दीप प्रज्ज्वलन के साथ ही कुलगुरू प्रो. स्मिता सहस्त्रबुद्धे ने अतिथियों का स्वागत कर राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रो. राकेश कुशवाह सहित साधारण परिषद, कार्य परिषद एवं विद्यार्थी परिषद के सदस्यगण उपस्थित थे।

यूजीसी की एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर शिकायत- हॉस्टल में लड़कियां लाते हैं सीनियर

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी के बीटेक स्टूडेंट्स ने सीनियर्स पर रैगिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं। ये छात्र यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (यूआईटी) के हैं। पीड़ित छात्र ने यूजीसी एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर शिकायत पर की है। छात्र ने शिकायत में दो छात्रों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे हॉस्टल में लड़कियों को लाते हैं और गांजा-शराब भी लाते हैं। ये लोग जूनियर्स को गांजा पीने के लिए मजबूर करते हैं। इसको जूनियर विरोध करने कोशिश करते हैं वो पीटते हैं। उसने शिकायत में कहा कि उसके साथ हाल ही रैगिंग की गई, जिससे उसे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत अधिक आघात पहुंचा है। जिन दो छात्रों पर आरोप लगाया है, उनमें एक बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के आठवें सेमेस्टर का और दूसरा बीटेक इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के आठवें सेमेस्टर का छात्र है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि यदि इन सीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो आत्महत्या कर लेगा। हालांकि शिकायतकर्ता ने हॉस्टल का नाम उजागर नहीं किया है। यूजीसी हेल्पलाइन की ओर से इस शिकायत को यूनिवर्सिटी प्रशासन के अलावा पुलिस प्रशासन को फॉरवर्ड की गई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा इस मामले की छानबीन की जाएगी। यूआईटी प्रबंधन का कहना है कि अभी उन्हें जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

मंदसौर में पहला कृषि उद्योग समागम

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मंदसौर में शनिवार को प्रदेश का पहला कृषि-उद्योग समागम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने सीतामऊ में आयोजित कार्यक्रम में फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यमियों से संवाद किया। इस दौरान 3,812 करोड़ रुपए के निवेश से 11 औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन किया गया। इन उद्योगों से मंदसौर, नीमच और आसपास के इलाकों में करीब 15,350 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को बिजली में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। अब वे सौर ऊर्जा से बिजली बनाएंगे और अपने पंप चलाएंगे। जरूरत से अधिक बिजली का राज्य सरकार खरीद करेगी और भुगतान भी करेगी। सीएम ने कहा कि किसान फलोद्यान, उद्यानिकी और फूड प्रोसेसिंग से जुड़ें। हर जिले में 'वृंदावन ग्राम' विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने दूधाखेड़ी में देवी लोक बनाने की घोषणा भी की। यहां 400 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। शामगढ़-सुवासरा और ताखाजी सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार भी शामिल है।

आदेश जल्द वापस नहीं हुआ तो भोपाल में जुटेंगे मेडिकल टीचर्स

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। डॉ. अरुणा कुमार को डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन (डीएमई) बनाने का विरोध जारी है। शनिवार को जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन (जूडा) और मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन (एमटीए) ने हमीदिया अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद एमटीए मध्यप्रदेश की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि अगर सरकार ने सोमवार तक डॉ. अरुणा कुमार को डीएमई बनाने का आदेश वापस नहीं लिया, तो उग्र आंदोलन होगा। एमटीए भोपाल के अध्यक्ष डॉ. राकेश मालवीय का कहना है कि प्रदेश के सभी 18 सरकारी और स्वशासी मेडिकल कॉलेजों से एमटीए के पदाधिकारी राजधानी के लिए कूच करेंगे। यहां एक मंच पर एकत्र होकर धरना देंगे।

भोपाल में 8000 पेड़ों की कटाई के खिलाफ आंदोलन

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। भोपाल के रत्नागिरी तिराहे से आशाराम नगर तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत 8000 पेड़ों की कटाई के विरोध में रविवार को शहरवासियों ने एकजुट होकर पर्यावरण बचाने का मुहिम शुरू किया है। शाम 5:30 बजे बड़ी संख्या में लोग रत्नागिरी तिराहे पर पहुंचे और पेड़ों को रक्षासूत्र बांधकर उन्हें बचाने का संकल्प लिया। इस आयोजन की अगुआई श्रमिक नेता दीपक गुप्ता ने की। उन्होंने कहा, यह सिर्फ पेड़ों की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हम इन पेड़ों को कटने नहीं देंगे। दीपक गुप्ता ने खुद पेड़ों को रक्षासूत्र बांधते हुए आंदोलन की शुरुआत की। इस अवसर

पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी पेड़ को रक्षा सूत्र बांधते हुए कहा- सरकार को चाहिए कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए। अगर 8000 पेड़ काटे गए तो भोपाल की हरियाली और जलवायु संतुलन पर गहरा असर पड़ेगा। आंदोलन में प्रकाश चौकसे, सुशील प्रजापति, उपेंद्र सिंह, सतीश कनोजिया, रामपाल धोसले, राकेश राजोरिया, महेश पंडित, योगेंद्र कौशल, पीएन उपाध्याय, ओंकार सिंह, कमलेश यादव, प्रायदूम तिवारी, योगेश यादव सहित सैकड़ों पर्यावरण प्रेमी शामिल हुए। वृक्ष बचाओ - जीवन बचाओ नारे के साथ यह जनांदोलन धीरे-धीरे शहर के कोने-कोने तक पहुंचता जा रहा है।

निराश्रित मरीजों के लिए हमीदिया में वार्ड नहीं

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। हमीदिया अस्पताल में लावारिस और निराश्रित मरीजों को इलाज में परेशानी न हो, इसको ध्यान में रखते हुए ऐसे मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाने को कहा गया था। लेकिन अब तक ऐसा कोई वार्ड नहीं बनाया गया है। अभी हालात ऐसे हैं कि किसी लावारिस और निराश्रित मरीज को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराना चाहते हैं तो इमरजेंसी एंबुलेंस 108 वाले मरीज को ले जाने को तैयार नहीं होते हैं। इसकी वजह हमीदिया अस्पताल में ऐसे मरीजों को भर्ती न करना है। लावारिस और निराश्रित मरीजों के लिए अस्पताल की इमरजेंसी में दो बेड आरक्षित किए गए हैं। ऐसे में यहां एक वक्त में दो से ज्यादा मरीजों को रखा नहीं जा सकता है। सामाजिक न्याय विभाग की ओर से 13 जनवरी को हमीदिया अस्पताल को पत्र लिखा गया था। लेकिन अब तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। ऐसे मरीजों की देखभाल के लिए अस्पताल में विभाग की ओर से 12 सोशल वर्कर तैनात किए गए हैं। सरकार इनकी सैलरी पर हर महीने लाखों रुपए खर्च करती है। लेकिन इनकी जहां-तहां ड्यूटी पर लगा दी जाती है। भोपाल टॉकीज ब्रिज के पास एक 65 वर्षीय बुजुर्ग को बस ने टक्कर मार दी। हाथ और पैर में चोट लगी थी। 26 अप्रैल को सोशल वर्कर बुजुर्ग को लेकर

हमीदिया अस्पताल पहुंचे। यहां इमरजेंसी में उनका इलाज किया गया। अभी तक बुजुर्ग चलने-फिरने की स्थिति में नहीं हैं। बावजूद इसके, अस्पताल स्टाफ की ओर से सोशल वर्कर को कहा जा रहा है कि आप इन्हें लेकर जाएं। नहीं तो हमें उनको अस्पताल से हटाना पड़ेगा। वरिष्ठ अधिकारियों को कॉल करने पर किया भर्ती... शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे 55 वर्षीय बुजुर्ग, जिसका गाल पूरी तरह सड़ा हुआ था, बैरागढ़ में मुख्य सड़क किनारे मिला। स्थानीय रहवासी सरजन नागर ने इसकी सूचना 108 एंबुलेंस को दी। मौके पर आई एंबुलेंस का ईएमटी महेश वर्मा मरीज को हमीदिया अस्पताल ले जाने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि हमीदिया अस्पताल वाले लावारिस मरीजों को भर्ती नहीं करते हैं।

लाल फीते में फंसी हैं 50 हजार फाइलें, इनमें 12 हजार से ज्यादा केस पेंशन के

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। लालफीताशाही के चलते मप्र के तमाम सरकारी विभागों में 50 हजार से ज्यादा मामले 6 महीने से लेकर सालभर से फाइलों में कैद हैं। बड़े विभागों में सबसे ज्यादा 12 हजार मामले हर साल पेंशन प्रकरणों के होते हैं। इसके बाद नंबर आता है राजस्व प्रकरणों का, जिनकी संख्या करीब 10 हजार है। स्कूल शिक्षा, लोक निर्माण, स्वास्थ्य और जल संसाधन जैसे विभागों में 12 हजार से ज्यादा मामले लंबित हैं। अन्य विभागों में यह संख्या 16 हजार के करीब है। खुद सरकार की समीक्षा में यह बात सामने आई है। प्रदेश में हर महीने करीब दो हजार कर्मचारी रिटायर होते हैं। इनमें से एक हजार के पेंशन पीपीओ इसलिए जारी नहीं होते क्योंकि विभाग एनओसी ही जारी नहीं करते हैं। यह स्थिति तब है जब पेंशन संचालनालय द्वारा विभागाध्यक्ष और कलेक्टरों को और वित्त विभाग के द्वारा विभागों को बार-बार रिमाइंडर जारी किए जा रहे हैं कि वे रिटायरमेंट के दिन ही कर्मचारी के प्रकरण का निपटारा कर वित्त को भेजें ताकि 10 दिन के भीतर पीपीओ जारी किए जा सकें। एमएसएमई विभाग में एमएस मेवाड़ को 35 साल सेवा के बाद चौथा समयमान-वेतनमान मिलना था। फाइल मूवमेंट शुरू हुआ 8 नवंबर 2024 को। उप सचिव ने 22 जनवरी 2025 को फाइल सचिव को भेजी। सचिव ने 31 जनवरी 2025 को फाइल प्रमुख सचिव को भेज दी। तब से फाइल वहीं है। जबकि इस पर अनुमोदन ई-फाइल के माध्यम से एक क्लिक में होना है। मेवाड़ रिटायर हो गए। अब कोर्ट की शरण में जाने के लिए मजबूर हैं। इसी तरह अपर संचालक पद से रिटायर हुए सीएस ध्रुवे, संयुक्त संचालक निरंजन श्रीवास्तव और उप संचालक दीप सिंह का पेंशन का प्रकरण लंबित है। राजस्व के मामलों की पेंडेंसी 6 महीने से साल भर तक की है।

मोहासा एनर्जी पार्क में आया 17000 करोड़ रु. का निवेश

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। नर्मदापुरम के मोहासा में विकसित हो रहे सोलर एनर्जी पार्क में बीते कुछ महीनों में लगभग 17 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। नौ कंपनियों को 450 एकड़ जमीन दी गई है। इन प्रोजेक्ट्स के शुरू होने पर लगभग 20 हजार नौकरियां मिलेंगी। पार्क में सोलर एनर्जी से जुड़े फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक मॉड्यूल और सिलिकॉन वेफर भी बनेंगे। साल 2023 में केंद्र ने पावर-रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को मंजूरी दी थी। सोलर पैनल, विंड टनल और बैटरी आदि की मैन्युफैक्चरिंग के लिए निवेश आकर्षित करने हेतु यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। लगातार निवेश प्रस्ताव मिलने से अब इस पार्क की पूरी जमीन अलॉट हो चुकी है। सोलर उपकरण के अलावा पार्क में केंद्र सोलर पीवी मॉड्यूल टेस्टिंग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, विंड टनल कैलिब्रेशन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी और बैटरी टेक्नोलॉजी टेस्टिंग के लिए सेंट्रल पॉवर रिसर्च इंस्टीट्यूट की मदद से तीन सेंटर बनाएगा। ग्रु एनर्जी, लैंडस्मिल ग्रीन इंडस्ट्री, इंसुलेशन ग्रीन एनर्जी, प्रीमियर एनर्जी ग्लोबल एनवायरनमेंट, सात्विक सोलर, सनकाइंड फोटोवोल्टिक, रेज ग्रीन एनर्जी, शक्ति एनर्जी और अल्पेक्स सोलर लिमिटेड ने पार्क में प्रोजेक्ट के लिए निवेश किया है।

भोपाल का रविंद्र भवन ठहाकों की गूंजा

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। रविंद्र भवन ठहाकों से गूंज उठा जब मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन गौरव गुप्ता ने अपने चिर-परिचित अंदाज में गुप्ता जी शो के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। शाम 6 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में भोपाल के अलावा पचमढ़ी और करीब 200 किलोमीटर दूर से भी दर्शक बड़ी संख्या में पहुंचे। कार्यक्रम में सैकड़ों की भीड़ उमड़ी, जो शुरू से अंत तक हंसी के माहौल में डूबी रही।

गौरव गुप्ता ने शो की शुरुआत शादी और घरजमाई जैसे संवेदनशील लेकिन मजेदार विषयों पर चुटीले चुटकुलों से की। उन्होंने विवाह, इंटर-कास्ट मैरिज, पेरेंटिंग और रोजमर्रा की

जद्दोजहद को बेहद हल्के-फुल्के और व्यंग्यात्मक अंदाज में पेश किया, जिसे सुनकर दर्शक ठहाकों पर काबू नहीं रख सके।

शो के दौरान गौरव ने दर्शकों से सीधा संवाद भी किया। ऑडिटोरियम में मौजूद इंटर-कास्ट मैरिज करने वाले कपल्स से उन्होंने हंसी-मजाक में बातचीत की और मंच पर सहजता से व्यंग्य का तड़का लगाया। उन्होंने कहा, मारवाड़ी, बनिया और जैनी-मोमोज, डंपलिंग्स और डिमसम की तरह एक जैसे ही होते हैं, जिस पर पूरा ऑडिटोरियम ठहाकों से गूंज उठा। एक कश्मीरी दर्शक से बात करते हुए गौरव ने चुटीले अंदाज में पूछा, कश्मीरी? हमारे वाले? और फिर मजाकिया लहजे में 'कलमा पढ़ने' की बात कही। इसी दौरान एक मलयाली दर्शक से संवाद करते हुए उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के भाषा-भेद पर हास्यात्मक टिप्पणियां कीं। गौरव ने चिकित्सा पेशे को भी अपने व्यंग्य का विषय बनाते हुए कहा, दर्शकों में डॉक्टरों की इतनी संख्या देखकर लग रहा है कि आज भोपाल में कोई अस्पताल ही नहीं खुला। शो में यश बदलनी, बादल समेत कई अन्य कॉमेडियनों ने भी मंच साझा किया और दर्शकों को गुदगुदाया। गौरव गुप्ता की खासियत है कि वे जिंदगी की जटिलताओं को ऐसे अंदाज में पेश करते हैं कि गंभीर मुद्दे भी हंसी में बदल जाते हैं। शादी की उलझनों से लेकर ऑफिस की झिकझिक तक, हर विषय को उन्होंने एक अलग नजरिए से छुआ।

नगरीय विकास मंत्री ने भवनों की सुरक्षा के लिये निकाय अधिकारियों को दिये निर्देश

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश में निश्चित ऊँचाई से बड़े भवनों में अग्नि दुर्घटना से बचाव के इंतजामों का निरीक्षण करने और नियमों की अनदेखी करने वाले भवनों को चिन्हित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से इस कार्य को प्राथमिकता दिये जाने के लिये कहा है।

प्रदेश में फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने के संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जारी निर्देश के अनुसार भवन स्वामी अब 31 दिसम्बर, 2025 तक फायर प्लॉन प्रस्तुत कर संबंधित अग्निशमन प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर सकेंगे। नियत तिथि के बाद फायर प्लॉन प्रस्तुत नहीं करने वाले भवन स्वामियों के विरुद्ध दण्ड के अधिरोपण की कार्रवाई नियत नियम के अनुसार की जायेगी। निर्देशों में कहा गया है कि फायर सेफ्टी प्लॉन के कण्डिका क्रमांक-2 में उल्लेखित भवन, जो कि पूर्व से निर्मित हैं, उन्हें 2 माह के भीतर एनबीसी से निर्धारित मानक अनुसार फायर प्लॉन तैयार कर अनुमोदन के लिये अग्निशमन प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। निर्देश में यह भी बताया गया है कि अग्निशमन अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ति के एक माह के भीतर फायर प्लॉन का अनुमोदन किया जायेगा। कण्डिका में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 2 माह की समयावधि के भीतर यदि भवन स्वामी फायर प्लॉन तैयार कर अग्निशमन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है, तो विलंब शुल्क के साथ 500 रुपये प्रतिदिन की दर से और एक वर्ष के बाद एक हजार रुपये प्रतिदिन की दर पर दण्ड शुल्क देय होगा। राज्य शासन ने नगर निगमों के लिये आयुक्त नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद और नगर परिषद के लिये संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले प्रकरणों के लिये जिला कलेक्टर और छावनी परिषद क्षेत्र जबलपुर, महू, मुरार, पचमढ़ी और सागर के लिये अधिशासी अधिकारी को अग्निशमन प्राधिकारी घोषित किया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जिन भवनों के लिये फायर सेफ्टी प्लॉन के प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है, उनमें 15 मीटर से ऊँचे समस्त भवन, एक तल पर 500 रू2 से अधिक निर्मित क्षेत्रफल वाले समस्त भवन (आवासीय एवं धार्मिक और सामुदायिक भवनों को छोड़कर) शामिल किये गये हैं। कोई भी होटल और अस्पताल, जिसमें 50 से अधिक पलंग और बिस्तर हों, उन्हें भी शामिल किया गया है।

जिला अस्पताल जैसे अपग्रेड होंगे सिविल हॉस्पिटल, बढ़ेंगी सुविधाएं

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। शहर के सिविल अस्पतालों को जिला अस्पतालों की तर्ज पर अपग्रेड करने की तैयारी है। इसके लिए सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी ने प्रमुख सचिव सहित अन्य अफसरों को प्रस्ताव भेजा है। इसके बाद लोगों को उनके घर के आसपास ही जिला अस्पताल जैसी मेडिकल सुविधाएं मुहैया हो सकेंगी।

इसमें सिविल अस्पताल बैरागढ़, कोलार, गोविंदपुरा और बैरसिया के अलावा 4 अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जिला अस्पताल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इनमें कटारा हिल्स, रातीबड़, मिसरोद व लंबाखेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं।

भोपाल की करीब 30 लाख आबादी में से 23 लाख शहरी आबादी है। ग्रामीण इलाकों के लिए विकासखंड स्तर की व्यवस्था लागू है, लेकिन शहरी क्षेत्र में इस तरह का कोई स्पष्ट ढांचा नहीं है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन, निगरानी और मूल्यांकन का काम

अकेले सीएमएचओ के भरोसे रहता है।

सीएमएचओ से नीचे कोई भी विभागीय निगरानी तंत्र न होने से व्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं। इसे देखते हुए जिले के स्वास्थ्य महकमे ने शहर में 8 शहरी स्वास्थ्य विकासखंड (अर्बन हेल्थ ब्लॉक) बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। इसमें शहर को 8 ब्लॉकों में बांटकर वहां मौजूद सिविल अस्पतालों को जिला अस्पताल की तर्ज पर अपग्रेड करने के अलावा हर ब्लॉक के लिए एक अनुविभागीय स्वास्थ्य अधिकारी, लोक स्वास्थ्य प्रबंधक और अन्य स्टाफ नियुक्त करने की बात है।

1 मई से खुलने थे, कैबिनेट में निर्णय के 4 दिन बाद पॉलिसी

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। कैबिनेट से मंजूरी के चार दिन बाद, शनिवार देर शाम मोहन सरकार ने प्रदेश की नई ट्रांसफर नीति जारी कर दी। इसमें जिलों के अंदर होने वाले तबादलों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब कलेक्टरों को प्रभारी मंत्रियों से अनुमोदन नहीं लेना होगा। सिर्फ सहमति लेना ही पर्याप्त होगा। यानी तबादले की जानकारी देकर सहमति ली जा सकेगी। इससे कलेक्टरों के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे और प्रक्रिया सरल होगी।

दरअसल, ट्रांसफर पालिसी का प्रारूप 29 अप्रैल को कैबिनेट में रखा गया था। उसमें प्रस्ताव था कि जिलों के अंदर सभी तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से ही किए जाएं। इससे कलेक्टरों के अधिकार सीमित हो जाते। लेकिन उच्च स्तर पर मंथन के बाद सरकार ने यह शर्त बदल दी। अब अंतिम नीति में अनुमोदन की जगह सहमति का प्रावधान किया गया है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जब नीति जारी हो चुकी है, तब प्रदेश में ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।

अब कलेक्टर अपने जिले में ज्वाइंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व अतिरिक्त तहसीलदार का तबादला कर सकेंगे।

चिकित्सकीय सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए समयानुसार नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां कराने के निर्देश

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़, सुलभ एवं जनोन्मुखी बनाने के लिए कृतसंकल्पित है और इस दिशा में मानव संसाधन की नियमित उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों में अनावश्यक विलंब न हो, यह प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मंत्रालय भोपाल में स्वास्थ्य विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि परिणाम घोषित होने के पश्चात नियुक्ति में तत्परता बरती जाए एवं समस्त आवश्यक औपचारिकताओं की शीघ्र पूर्ति सुनिश्चित की जाए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए चिकित्सकीय मैनपावर की पर्याप्त उपलब्धता अनिवार्य है। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। हर दिन महत्वपूर्ण है, इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया की दैनिक समीक्षा एवं फॉलो-अप किया जाए। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव, आयुक्त स्वास्थ्य श्री तरुण राठी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की प्रबंध संचालक डॉ. सलोनी सिडाना सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

नर्सिंग घोटाले की दोषी परीक्षक के खिलाफ एनएसयूआई और छात्रों ने जताया विरोध

प्रायोगिक परीक्षा पुनः कराने की मांग

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। आज रीवा स्थित शासकीय नर्सिंग कॉलेज में प्रायोगिक परीक्षा लेने पहुंची दतिया शासकीय नर्सिंग कॉलेज की स्टाफ चंद्रकला दिवगैया के खिलाफ एनएसयूआई और नर्सिंग छात्रों ने विरोध जताया । यह वही चंद्रकला दिवगैया हैं जो नर्सिंग काउंसिल की पूर्व रजिस्ट्रार रहीं इनके कार्यकाल में कई फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई थी विभाग ने इनको दोषी करार करते हुए निलंबित कर दिया था विभाग इनकी गहन जांच भी कर रहा हैं ।

एनएसयूआई रीवा के जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने इस मुद्दे पर तीखी आपत्ति जताई और कहा कि "नर्सिंग घोटाले की दोषी किसी भी स्थिति में परीक्षक नहीं हो सकती। यदि ऐसे व्यक्ति छात्रों की परीक्षा लेंगे, तो परीक्षा की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठेंगे और बड़े स्तर पर गड़बड़ी की आशंका बनी रहेगी। पंकज उपाध्याय ने आगे कहा कि हस्द्ध छात्रों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और मांग की कि प्रायोगिक परीक्षा को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर, किसी निष्पक्ष एवं स्वच्छ छवि वाले परीक्षक के माध्यम से पुनः आयोजित किया जाए। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा।

कलेक्टर मऊगंज ने दैनिक वेतनभोगियों की नई दरें की घोषित

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। कलेक्टर मऊगंज संजय कुमार जैन ने शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये एक अप्रैल 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक की अवधि के लिए दैनिक वेतन की नई दरें निर्धारित की गई हैं। इन दरों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है। यह दरें मासिक, दैनिक तथा अंशकालिक एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और श्रमिकों पर लागू होंगी।

निर्धारित नई वेतन दरें - अकुशल कर्मचारियों के लिये न्यूनतम मूल वेतन 9575 रूपये तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 2550 रूपये के साथ प्रतिमाह कुल 12125 रूपये निर्धारित किया गया है। अर्द्धकुशल के लिये न्यूनतम मूल वेतन प्रतिमाह 10557 रूपये तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 2550 रूपये के साथ कुल वेतन 13121 रूपये निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार कुशल के लिये न्यूनतम मूल वेतन 12294 रूपये तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 2550 रुपए के साथ प्रतिमाह कुल 14844 रूपये वेतन देय होगा। उच्च कुशल के लिये प्रतिमाह 13919 रूपये न्यूनतम मूल वेतन तथा 2550 रूपये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सहित कुल 16469 रूपये कुल वेतन देय होगा। मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउंड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। कृषि नियोजन के लिए अकुशल मजदूर की मजदूरी 7660 रुपए तथा 2268 रुपए मंहगाई भत्ते के साथ कुल 9928 रुपए प्रतिमाह निर्धारित की गई है। इसकी दैनिक मजदूरी मूल वेतन 255.33 रुपए तथा मंहगाई भत्ता 75.60 रुपए सहित 331 रुपए प्रतिदिन देय होगी। महिला एवं पुरूषों के लिए वेतन की दरें समान रहेंगी।

"आईजी आपके द्वार" जन चौपाल का हुआ आयोजन

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा रेंज के आईजी गौरव राजपूत ने नवाचार करते हुए प्रत्येक जिले में निर्धारित स्थल पर जाकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा आमजनता से संवाद की पहल की है। इसके लिए थाना क्षेत्र में निर्धारित दिवसों में जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। मैहर के ग्राम पहाड़ी में आईजी श्री राजपूत ने आपके द्वार जन चौपाल का प्रथम आयोजन किया। आईजी ने कार्यक्रम में आमजनता से कानून और व्यवस्था बनाये रखने, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाने और अपराधों पर नियंत्रण के संबंध में आमजनता से संवाद किया। आमजनता को साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूक रहने की समझाइश दी गयी। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक मैहर सुधीर अग्रवाल, सीएसपी राजीव पाठक सहित पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

मातृशक्ति ने ली यूथ हैल्पिंग हैंडस संस्था की सदस्यता

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। यूथ हैल्पिंग हैंडस सतना की एक विशेष बैठक 5 मई सोमवार को होटल उमा रेजीडेंसी में सम्पन्न हुई बैठक में संस्था की वोमेन विंग का गठन किया गया

डॉ. लक्ष्मी मोहनानी,डॉ मनीषा सोई,ज्योति मनवानी,डोली बमरी,डॉ एकता वाधवानी,डॉ आकृति गुप्ता, माधुरी शर्मा,सुहानी वलेचा,अक्षरा दासानी,एकता साहनी,श्वेता तिवारी श्रद्धा भीमनानी ने सदस्यता ली

संस्था संस्थापक श्री रूपेश वलेचा ने जानकारी देते हुए बताया आगामी जून माह में मेधावी छात्रा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। बैठक में संस्था के सदस्य मनीष असरानी,सोमेश आहूजा,अमन जैसवाल,अमित भवनानी,योगेश दासानी,अमित शर्मा, हिमांशु श्रीवास्तव,संजय खिलवानी, गुलाबराय नागदेव,सोनू नागदेव और राजेन्द्र गुप्ता उपस्थित थे।

बच्चों को संकट से बचाने और सहायता के लिए है चाइल्ड हेल्पलाइन 1098

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 बहुत जाना पहचाना नम्बर है। देश भर के लाखों संकटग्रस्त बच्चों के लिए यह आशा की किरण है। यह हेल्पलाइन नम्बर साल के सभी 365 दिनों में 24 घंटे निःशुल्क सहायता के लिए उपलब्ध है। इसका संचालन भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नोडल एजेंसी चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से पूरे देश में किया जाता है। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 से सहायता मांगने पर संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधिकारी और महिला एवं बाल विकास अधिकारी के पास में सूचना पहुंचती है। सूचना मिलने पर अन्य विभागों के सहयोग से बच्चों को संकट से बचाने तथा अन्य वांछित सहयोग देकर उनका संरक्षण किया जाता है। बच्चों को आपातकाल में मदद देने और आवश्यकता होने पर पुनर्वास केन्द्र की सुविधा देने में चाइल्ड हेल्पलाइन बहुत कारगर है। इसके माध्यम से बाल विवाह रोकने, बच्चों को नशे की लत से बचाने, बालश्रम पर रोक तथा अन्य कारणों से संकटग्रस्त बच्चों को सहायता दी जाती है। महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी कार्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा थानों में चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 का उल्लेख किया गया है। कोई भी व्यक्ति संकटग्रस्त बच्चों की सहायता करने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर में सूचना दे सकता है। यह हेल्पलाइन पूरी तरह से निःशुल्क कार्य करती है।

राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की मासिक बैठक का हुआ आयोजन

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की मासिक बैठक उद्यानिकी परिसद कोठी कम्पाउण्ड रीवा मे जिला अध्यक्ष भक्त प्रहलाद कुशवाहा की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुई।मासिक बैठक मे संगठन के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री रविदत्त सिंह मुख्य अतिथि के रूप मे उपस्थित रहें। शासन द्वारा द्वारा गेहूँ खरीदी का पोर्टल बन्द करा दिया गया था, इस सम्बन्ध मे किसान मजदूर महासंघ ग्राम काई माढौ की मासिक बैठक मे जानकारी आने पर प्रस्ताव पास कर शासन-प्रशासन को समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत कराया गया था, जिस वजह से 02 दिन, 04 या 05 मई 2025 को कलेक्ट्रेट रीवा मे स्लाट बुकिंग किये जाने का आदेश हुआ। किसानों की परेशानी को देखते हुये किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारी रीवा कमिश्नर से मिल कर अवगत कराया कि मालवा और मध्य भारत प्रांत से एक माह पीछे महाकौशल प्रांत की बोवाई-जोताई होती है और इस वर्ष 15 दिन देरी से नहर भी खोली गई थी, जिस वजह से कटाई-गहाई भी देरी से रही है। सरकार की नीति के मुताबिक पूरे मध्य प्रदेश मे खरीदी होना बताया गया, जबकि महाकौशल प्रांत के किसी भी जिले की 01 अप्रैल को कटाई ही नही शुरू हुई थी, इस वजह से गेहूँ खरीदी का समय सीमा उपरोक्त आधार पर कम से कम 15 दिन बढ़ाई जाय। जिससे शासन के मंशानुसार सभी किसानों का गेहूँ का अर्जन सुचारू रूप से सही हो सके, साथ ही सोसायटी का खाद और क्रेडिट कार्ड का पैसे का भुगतान समय सीमा मे हो सके। बैठक मे सर्व सम्मति से संगठन का स्थापना दिवस व संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक श्री शिव कुमार शर्मा (काका जी) का जन्म दिवस 28 मई 2025 को मनाने का निश्चय किया गया है, स्थान का चयन सिरमौर ब्लॉक की मासिक बैठक मे 17 मई 2025 को किया जायेगा। बैठक मे मुख्य रूप से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रविदत्त सिंह, महाकौशल प्रांत के अध्यक्ष शोभनाथ कुशवाहा, रीवा जिला अध्यक्ष भक्त प्रहलाद कुशवाहा, रीवा जिला कोषाध्यक्ष जगदीश प्रसद सोंधिया, मीडिया प्रभारी रीवा विवेक पटेल आदि लोग उपस्थित रहें।

सीधी में कृषि तथा संबद्ध विभागों की संभागीय बैठक आज

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। कमिश्नर बीएस जामोद की विशेष पहल पर कृषि, उद्यानिकी, मछलीपालन तथा पशुपालन विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों में संयुक्त संभागीय बैठकें एवं प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें जिला तथा विकासखण्ड स्तर के अधिकारी इन सभी विभागों की योजनाओं की जानकारी लेने के साथ इनके क्रियान्वयन में अपनी भूमिका का निर्धारण कर रहे हैं। इस क्रम में अब तक रीवा, मऊगंज, मैहर तथा सतना जिलों में बैठकों का आयोजन किया जा चुका है। इस संबंध में संयुक्त संचालक कृषि जेएस नेताम ने बताया कि सीधी में 6 मई को संयुक्त बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जा रही हैं। इनमें संबंधित विभागों के संभागीय अधिकारी, जिला तथा विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी शामिल होंगे।

नरवाई में आग लगाने वालों पर होगी कठोर कार्यवाही

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जिले में कृषकों तथा पशुपालकों को भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा गर्मियों में होने वाली आग की दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा नरवाई जलाने पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए जा चुके हैं। यह आदेश सम्पूर्ण रीवा जिले में 17 मार्च से लागू है। आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए हैं। प्रतिबंध का उल्लंघन करके नरवाई जलाने पर दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर 2500 रुपए, दो से पाँच एकड़ तक के किसानों पर 5000 रुपए तथा पाँच एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों पर 15000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। आदेश की व्यक्तिशः तामीली संभव नहीं होने के कारण इसे भारतीय नागरिक संहिता की 2023 धारा 163 (2) के तहत आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। विभिन्न संचार माध्यमों से इसकी सूचना आमजनता को दी गई है।

जारी आदेश के अनुसार रबी फसलों की कटाई के बाद खेतों को आग के हवाले करने वाले किसानों के खिलाफ अब कठोर कार्यवाही की जाएगी। हार्वेस्टर के माध्यम से गेंहू की कटाई करने पर उसमें स्ट्रारीपर लगाना अनिवार्य होगा। जिन हार्वेस्टरों में अवशेष प्रबंधन सिस्टम नही होगा, उन्हें गेंहू काटने की अनुमति नही दी जायेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। जिले में चलने वाले कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रारीपर लगाना अनिवार्य होगा। जिला परिवहन अधिकारी इसकी निगरानी करें। इसका उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही करें। खेत में नरवाई जलाने से मिट्टी के कई लाभदायक सूक्ष्मजीव एवं जैविक कार्बन जलकर नष्ट हो जाते हैं। जिसके कारण मिट्टी कठोर हो जाती है। इसकी जल धारण क्षमता घट जाती है। इसलिए नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। नरवाई जलाने के स्थान पर इसको स्ट्रारीपर से भूसा बनाकर पशुओं के भोजन के रूप में उपयोग करें। किसान यदि गेंहू के बाद अन्य कोई फसल लेना चाहता है तो हैप्पी सीडर और सुपर सीडर से फसल की बोनी करे। इससे नरवाई मिट्टी में मिलकर खाद के रूप में फसल के लिए पोषण का कार्य करेगी। नरवाई को बेलर, रैकर एवं चापर मशीन की सहायता से बंडल बनाकर औद्योगिक ईधन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है।

जारी आदेश के अनुसार पर्यावरण विभाग द्वारा जारी 2017 के नोटिफिकेशन में नरवाई जलाने पर दण्ड आरोपित करने का प्रावधान किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा भी फसल अवशेष अथवा नरवाई को जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उल्लंघन करने पर किसान पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेश को पालन कराने के लिए अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। साथ ही सभी अनुभागों में एसडीएम की अध्यक्षता में निगरानी समिति गठित की गई है। आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए खण्ड स्तर पर नायब तहसीलदार, कृषि विस्तार अधिकारी एवं थाना प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई है। जिला दण्डाधिकारी ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को पटवारी के साथ नरवाई जलाने की घटनाओं का प्रतिवेदन तैयार कर तहसीलदार को भेजने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार नरवाई जलाने वाले किसानों की सुनवाई करके एसडीएम के माध्यम से अंतिम निराकरण के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक एवं समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व), तहसीलदार एवं कृषि विभाग के संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है।

जल स्त्रोतों की सफाई और खेत तालाबों का हो रहा निर्माण

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा और मऊगंज जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एक ओर नदियों के उ–म स्थल तथा जल कुण्डों एवं कुओं की साफ-सफाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर वर्षा के जल को संचित करने के लिए खेत तालाब एवं अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। कुंओं और ट्यूबवेलों में रिचार्ज पिट बनाकर भी पानी को सहेजने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मऊगंज जिले में ग्राम बाराती और गढ़वा में पाँच किसानों के खेतों में जनपद पंचायत के उपयंत्री द्वारा खेत तालाब निर्माण का लेआउट दिया गया। नईगढ़ी विकासखण्ड में ग्राम अकौरी में जन अभियान परिषद और महिला स्वसहायता समूहों ने मिलकर मटिहरा नदी की साफ-सफाई और पुनर्जीवन कार्य में श्रमदान किया। जल चौपाल और रैली के माध्यम से जल संरक्षण के संदेश दिए गए। जन अभियान परिषद ने रीवा जिले के सिरमौर विकासखण्ड में ग्राम बगढा दुबे में ग्रामीणों के सहयोग से झिरिया कुण्ड की साफ-सफाई तथा जीर्णोद्धार का कार्य संपन्न किया। जवा विकासखण्ड के ग्राम दिव्यगवां में किसानों के साथ जल संवाद का आयोजन करके उन्हें कम पानी में अच्छी उपज देने वाली फसलों की जानकारी दी गई।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरक्षण के कार्यों के साथ-साथ पानी को बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। जन अभियान परिषद तथा मंगल युवा कल्याण समिति ने जवा विकासखण्ड के ग्राम ऊंचा डीह में रैली निकालकर जल संरक्षण का संदेश दिया साथ ही ग्राम के खोखला तालाब में साफ-सफाई तथा गहरीकरण में श्रमदान किया। हनुमना विकासखण्ड के ग्राम सलैया खास में भी जल चौपाल का आयोजन किया गया। अभियान के तहत नईगढ़ी विकासखण्ड के ग्राम पिपरा में नाला ड्रिंचिंग का कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायत माड़ौ में आमजनता के सहयोग से तुर्रा नाले के सूखे पड़े पुराने जल स्रोत तथा बावड़ी की साफ-सफाई की गई। इसकी साफ-सफाई और पत्थर तोड़ने के बाद जल स्रोत से पुनः पानी की अविरल धारा शुरू हो गई है। अभियान के तहत ग्राम फूल की हरिजन बस्ती और बस स्टैण्ड में ग्राम पंचायत तथा पीएचई विभाग ने मिलकर पेयजल की व्यवस्था की। अभियान के तहत मनरेगा के 29 अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा कराकर उनका पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया। जनपद पंचायत मऊगंज की ग्राम पंचायत ऊधापुरवा में तीन किसानों के खेतों में खेत तालाब का निर्माण शुरू कराया गया। इसी तरह जिले भर में जल संरक्षण के कार्य लगातार किए जा रहे हैं।

विचार

भारत संकल्प की सराहना करता है मगर इंतजार लम्बा

पिछले रविवार को प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम में मुख्य रूप से कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और उसके बाद की घटनाओं पर चर्चा की गई। खबरों के अनुसार, मोदी ने कहा, ''हर भारतीय पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना रखता है। चाहे वह किसी भी राज्य से हो, चाहे वह कोई भी भाषा बोलता हो,वह उन लोगों का दर्द महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं महसूस कर सकता हूं कि आतंकवादी हमले की तस्वीरें देखकर हर भारतीय का खून खौल रहा है।'' प्रधानमंत्री ने पूरे देश की भावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने भारत के लोगों की एकता, एकजुटता और संकल्प के बारे में बात की और वादा किया कि एक राष्ट के रूप में भारत अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करेगा। मैं उनके दृढ़ शब्दों की सराहना करता हूं। अतिशयोक्तिपूर्ण दावे ‐ लेकिन, मुझे डर है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा, वह सब सही नहीं था। हमले से पहले कश्मीर की स्थिति पर, मोदी ने कहा, ''कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूलों और कालेजों में रौनक थी, निर्माण कार्य ने अभूतपूर्व गति पकड़ी थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या रिकॉर्ड दर से बढ़ रही थी, लोगों की आय बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे थे'' सभी लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे और गहन ड्क्षचतन के क्षणों में मोदी भी इन दावों को अतिशयोक्ति मानेंगे।

भारत इंतजार कर रहा है – कश्मीर में शांति दूर की कौड़ी है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जून 2014 से मई 2024 के बीच के दशक में 1,643 आतंकवादी घटनाएं हुईं, 1,925 घुसपैठ की कोशिशें हुईं, 726 सफल घुसपैठ हुईं और 576 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। स्कूलों में कोई जीवंतता नहीं थी। ए.एस.ई.आर. 2024 की रिपोर्ट से पता चला कि 2018 के बाद सरकारी स्कूलों में नामांकन में गिरावट आई है और उच्च कक्षाओं में उन छात्रों का प्रतिशत खराब हो गया है जो कक्षा 2 की पाठ्य सामग्री पढ़ सकते थे। सबसे विवादास्पद दावा यह था कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। जम्मू-कश्मीर का दर्जा घटाकर केंद्र शासित प्रदेश कर दिए जाने के बाद से लोकतंत्र वास्तव में कम हो गया है। जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र आधा है, जहां उप-राज्यपाल के पास बहुत अधिक शक्तियां हैं जो मंत्रिपरिषद और निर्वाचित प्रतिनिधियों को नहीं दी गई हैं। राज्य का दर्जा छीनना और चुनाव के बाद बहाली का अधूरा वादा एक निरंतर अपमान है जो लोगों को परेशान करता है।2023-24 में जम्मू-कश्मीर की आधिकारिक बेरोजगारी दर 6.1 प्रतिशत थी। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से नीचे बनी हुई है। हालांकि, यह सच है कि पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन आतंकवादी हमले के कारण इसमें बाधा उत्पन्न हो गई है।

जाति जनगणना विभाजन का नहीं, विकास का आधार बने

पहलगाम की क्रूर एवं बर्बर आतंकी घटना के बाद मोदी सरकार लगातार पाकिस्तान को करारा जबाव देने की तैयारी के अति जटिल एवं संवेदनशील दौर में एकाएक जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लेकर न विपक्षी दलों को बल्कि समूचे देश को चौकाया एवं चमत्कृत किया है। सरकार का यह निर्णय जितना बड़ा है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। मोदी सरकार का जातिगत जनगणना के लिए तैयार होना सुखद और स्वागतयोग्य है। पिछले कुछ समय से जातिगत जनगणना की मांग बहुत जोर-शोर से हो रही थी। कुछ राज्यों में तो भाजपा भी ऐसी जनगणना के पक्ष में दिखी थी, पर केंद्र सरकार का रुख इस पर बहुत साफ नहीं हो रहा था। अब अचानक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राजनीतिक मामलों की उच्चस्तरीय कैबिनेट समिति की बैठक में यह फैसला ले लिया गया। बाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि आगामी जनगणना में जातिगत गणना भी शामिल रहेगी। यह कदम जहां देश के राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को बदलेगा, वही सामाजिक असमानताओं को दूर करने और वंचित समुदायों के उत्थान के लिए लक्षित नीतियों को लागू करने में मील का पत्थर साबित होगा।

जातिगत जनगणना 1931 यानी अखंड भारत में अंग्रेजी सत्ता ने कराई थी। भारत में जनगणना की शुरुआत अंग्रेजी हुकूमत के दौर में, सन 1872 में हुई थी और 1931 तक हुई हर जनगणना में जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्ज किया गया। आजादी के बाद सन् 1951 में जब पहली बार जनगणना कराई गई, तो तय हुआ कि अब जाति से जुड़े आंकड़े नहीं जुटाए जाएंगे। स्वतंत्र भारत में हुई जनगणनाओं में केवल अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े डेटा को ही पब्लिश किया गया। 2011 में मनमोहन सरकार ने जातिवार जनगणना कराई अवश्य, लेकिन उसमें इतनी जटिलताएं एवं विसंगतियां मिलीं कि उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। इसके बाद कुछ राज्यों ने जातियों की गिनती करने के लिए सर्वे कराए, क्योंकि जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र को ही है। हालांकि भाजपा ने बिहार में जाति आधारित सर्वे का समर्थन किया, लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर वह मुखर नहीं रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अवश्य इसका समर्थन किया। लेकिन अब एकाएक भाजपा को जातिगत जनगणना करना अपने हित में दिखाई दिया क्योंकि अपनी नीतियों एवं योजनाओं के बल पर भाजपा ने पिछड़ी जातियों और दलितों की गोलबंदी कर सत्ता का सफर आसान बनाया है।

जातिगत जनगणना का भारतीय राजनीति और समाज-व्यवस्था पर व्यापक एवं दूरगामी प्रभाव पडेगा। कांग्रेस और कुछ क्षेत्रीय दल इसकी पुरजोर मांग करने में लगे हुए थे। सबसे ज्यादा जोर राहुल गांधी दे रहे थे, जबकि नेहरू से लेकर नरसिंह राव तक ने इसकी जरूरत नहीं समझी। यह तय है कि जातिगत जनगणना कराने के फैसले पर जहां कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दल इसका श्रेय लेना चाहेंगे, वहीं भाजपा इसे सामाजिक न्याय एवं समता-संतुलित समाज-निर्माण केंद्रित अपनी पहल बताएगी। जाति आधारित जनगणना सामाजिक न्याय में सहायक बनेगी या नहीं, लेकिन इससे जातिवादी राजनीति के नए दरवाजे खुलेंगे एवं आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राजनीति की धूरी बनेगा। कांग्रेस एवं विपक्षी दलों ने अपने संकीर्ण एवं स्वार्थी राजनीतिक नजरिये से यह मांग इसलिए उठाई थी ताकि इस आधार पर आगे आरक्षण के मुद्दे को गर्माया जा सके और जातीय गोलबंदी कर चुनावी फायदा लिया जा सके। लेकिन भाजपा-सरकार ने जाति जनगणना का ऐलान कर इस मुद्दे को अपनी पाली में ले लिया है। भले ही इसके आंकड़े आने के बाद आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग से भाजपा कैसे निपटेगी, यह बड़ी चुनौती उसके सामने है। वैसे भी इस तरह की पहल जिन राज्यों में हुई है, वहां भी इसे लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे विवाद भाजपा के लिये एक नयी चुनौती बनेंगे। जाति आधारित जनगणना से भारतीय समाज के नये कोने-अंतरे-चुनौतियां सामने आयेगी। लेकिन जातिगत जनगणना के समर्थकों का मानना है कि यह सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। जनगणना में दलितों और आदिवासियों की संख्या तो गिनी जाती है और उन्हें राजनीतिक आरक्षण भी मिला हुआ है लेकिन पिछड़ी और अति पिछड़ी (ओबीसी और ईबीसी) जातियों के कितने लोग देश में हैं इसकी गिनती नहीं होती है। जनगणना एक बहुत बड़ी कवायद है और अगर इसमें जातिगत गणना को भी शामिल किया जा रहा है, तो काम और भी सावधानी एवं सतर्कता से करना होगा। हजारों जातियां हैं और उनकी हजारों उप-जातियां हैं। सबको अलग-अलग गिनने के लिए देश को अपनी डिजिटल शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा।

निश्चित ही नयी राजनीतिक एवं नीतिगत स्थितियां समस्याएं खड़ी होगी। अब सभी जातियों की गिनती होगी। यह गिनती मुस्लिम, ईसाई और अन्य समुदायों में भी होनी चाहिए, क्योंकि कोई दावा कुछ भी करे, जाति और उसके आधार पर विभेद सब जगह है। इससे भी ज्यादा आवश्यक, बल्कि अनिवार्य यह है कि जातिगत जनगणना जातिवाद की राजनीति का हथियार न बने और वह भारतीय समाज को विभाजित न करने पाए। इस अंदेशे को दूर करने के कुछ ठोस उपाय होने ही चाहिए कि जाति आधारित जनगणना जातीय विभाजन का कारण न बनने पाए। यह अंदेशा इसलिए है, क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि कई राजनीतिक दल खुले रूप से जाति की राजनीति करते हैं। माना जाता है कि देश की आबादी में 52 फ़ीसदी लोग पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के हैं। ओबीसी समुदाय के नेताओं का मानना है कि इस हिसाब से उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी काफ़ी कम है। राजनीतिक दल इन समुदायों का समर्थन हासिल करने के लिए जाति जनगणना का समर्थन कर रहे हैं।

भारत में जाति जनगणना आजादी के बाद रुकी, पर अब सामाजिक न्याय, नीतिगत सुधार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। पारदर्शिता और सावधानी से किया गया यह कदम समावेशी विकास का आधार बन सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जाति आधारित जनगणना को एक समतामूलक समाज निर्माण के दृष्टिकोण से समर्थन देने के संकेत दिए हैं। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि यह संवदेनशील मामला है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक या चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि पिछड़ रहे समुदाय और जातियों के कल्याण के लिए होना चाहिए। जाति जनगणना के आंकडे प्रस्तुत होने से राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी कितनी कम है, यह डर संभवतः भाजपा को सता रहा था। लेकिन भाजपा का यह डर या तो ख़त्म हो गया है, या फिर उसने बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनावी लाभ लेने के लिए ये क़दम उठाया है। भाजपा इसके ख़िलाफ़ थी, उसने जातिगत जनगणना को देश को बांटने की कोशिश करने वाला बताया था। लेकिन एनडीए में शामिल भाजपा की ज्यादातर सहयोगी पार्टियां इसके पक्ष में हैं।

जातिगत जनगणना के आंकड़े 2026 या 2027 के अंत में आएंगे और तब तक बिहार और यूपी के चुनाव हो चुके होंगे। इसलिए इसका चुनावी लाभ लेने की बात सही नहीं है। वैसे भी भाजपा ने हाल के वर्षों में पिछड़ों और दलितों समुदाय को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। भाजपा इस जातिगत गणना से ये भी दिखाना चाहती है कि पिछड़ों के एक-आध समुदाय को छोड़ दें तो ओबीसी समुदाय का बड़ा हिस्सा उसके साथ है। वैसे तो विभिन्न राजनीतिक दल अमुक-अमुक जातियों का नेतृत्व करने के लिए केवल जाने ही नहीं जाते, बल्कि ऐसा दावा भी करते हैं। इसलिये जाति आधारित जनगणना का लाभ है तो हानि भी है। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि जातिगत जनगणना वंचितों-पिछड़ों के उत्थान में सहायक बने, लेकिन यदि वह विभाजन को बल देती है और देश की एकजुटता प्रभावित करती है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं होगा। जनगणना के आंकड़े सरकार और जनता के लिए खुले और पारदर्शी होने चाहिए, ताकि सामाजिक संबंधों, आर्थिक अवसरों और राजनीतिक गतिशीलता की नई एवं समानतामूलक दिशाएं उद्घाटित हो सके और भारतीय समाज की विविधता की एक व्यापक सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।

राजा को अवश्य ही 'प्रजा रक्षक ' होना होगा

आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत के सराहनीय बयान को पढ़ कर कुछ कहने का साहस हुआ। उन्होंने राजा के 'प्रजारक्षक' होने का आह्वान किया है। दूसरी बड़ी सटीक बात उन्होंने कही कि 'अड्क्षहसा' निर्बल का नहीं बलशाली व्यक्ति का गुण है। दुष्टों पर की गई 'हिंसा' 'अहिंसा' ही है। वीर पुरुष सदैव दुष्टों का नाश करता है परन्तु वह ड्क्षहसा नहीं बल्कि मानवता की रक्षा हेतु की गई 'अहिंसा' है। 'अहिंसा' को महात्मा गांधी ने अपनाया था। आइए हम सब मिल-बैठ कर राजा के 'प्रजा रक्षक' होने के विषय पर विचार करें। 'राजनीति' में 'राजा के दैवी सिद्धांत का भरपूर वर्णन हुआ है। 'माइट इज राइट' अर्थात 'मतस्य न्याय' की प्रधानता थी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसी अव्यवस्था से समाज नहीं चलता। प्रजा ने मिल-बैठ कर अपने में से एक व्यक्ति को अपना राजा चुन लिया। फिर राजा और प्रजा में एक संधि हुई जिसे 'राजा का दैवी सिद्धांत' कहा गया है। राजा प्रजा के लिए 'प्रभु' है। संधि के अनुसार प्रजा ने कहा कि आज से आप हमारे राजा हुए। आप को हमारी रक्षा करनी होगी।

प्रजा जब आराम से सो जाए तो तुम्हें प्रजा की रक्षा करनी होगी। हमारे घर, खेत-खलिहान, हमारी बहू-बेटियों को तुम्हें सुरक्षा देनी होगी। यह सब करने के लिए प्रजा अपने वीर पुत्र राजा को देगी। शासन चलाने के लिए राजा को टैक्स देंगे। जब कभी राजा पर संकट आएगा, प्रजा राजा से पूर्ण सहयोग करेगी। राजा ने कहा 'तथास्तु' ऐसा ही होगा। समाज राजा के राज्य में आगे बढ़ता चला गया। लोकतंत्र में भी प्रजा अपने राजा का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए करती है परन्तु राजा का 'दैवी सिद्धांत' लोकतंत्र में और ज्यादा मूल्यवान

हो गया। लोकतंत्र में राजा को अवश्य ही 'प्रजा रक्षक', 'प्रजा कल्याणकारी' और 'प्रजा हित चिंतक' होना होगा। दुष्टों का दमन करना ही होगा यद्यपि राजाओं, महाराजाओं और शहंशाहों के दौर समाप्त हो चुके हैं परन्तु लोकतंत्र में राजा को 'प्रजा कल्याण' लोगों के जीवन की 'रक्षा' अवश्य करनी होगी। अन्यथा अगले चुनाव में जनता प्रजा की रक्षा न करने वाले राजा को उतार फैंकेगी।

लोकतंत्र में आई.ए.एस., आई.पी.एस., गुप्तचर, विष कन्याएं, बड़े-बड़े अफसर प्रशासन चलाने के लिए राजा के सहायक होते हैं। पुलिस और सेना चौबीस घंटे राजा के हुक्म को मानने के लिए तत्पर रहते हैं। इतने सारे साधन, ऐसी युक्तियां होने पर भी जम्मू-कश्मीर में 1980 से लेकर 2025 तक की अवधि में वहां से राजा 'मिसिंग' दिखाई दिया। 30,000 लोगों की बेशकीमती जिंदगियां जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के हाथों मारी गईं। कश्मीर घाटी के मालिक 'कश्मीरी पंडितों' को वहां से निष्कासित कर दिया गया। उन कश्मीरी पंडितों के डंगर-डोर, घर-बाहर, खेत-खलिहान पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया।परन्तु न वहां राजा दिखाई दिया और न राजा का प्रशासन। सुना है राजा और प्रशासन की आंखें चौबीस घंटे खुली रहती हैं परन्तु जम्मू-कश्मीर राज्य में 1980 से 2025 के बीच न राजा दिखा न ही उसका प्रशासन। जम्मू-कश्मीर में सरेआम पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद होता है। रोज सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ें होती हैं परन्तु आतंकवादियों की लाइनें खत्म ही नहीं होतीं।

'रक्तबीज' की तरह पुनः पैदा हो जाते हैं। 1980 से सुनते आए हैं कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद आखिरी सांस ले रहा है। केवल 256 आतंकवादी ही शेष बचे हैं। उनका भी जल्द ही सफाया हो जाएगा। जम्मू-कश्मीर में 'राजा के दैवी सिद्धांत' को नरसंहार के रूप में पैरों तले रौंदा जा रहा है। जम्मू-कश्मीर में मानवता कराह रही है। राजा-प्रजा के बीच हुई संधि लाशों के ढेर पर खड़ी है। जम्मू-कश्मीर में राजा ने 'प्रजारक्षक' होने के सभी दावे ताक पर रख दिए हैं। कश्मीर घाटी में क्या सेना, क्या पुलिस, क्या कश्मीरी हिंदू, क्या कश्मीरी मुसलमान आतंकवाद की आंधी की चपेट में आ चुके हैं।

मीडिया, प्रैस हो या टैलीविजन आतंकवादियों द्वारा नरसंहार के दृश्य तो दिखाएंगे परन्तु इसका अंत कहां होगा। इस पर चुप्पी साध लेंगे। राजा जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खात्मे की बात पर ललकारते तो अवश्य हैं परन्तु धरातल पर आंसू छोड़ती मानवता के दर्द को हृदय से कोई महसूस नहीं करता। शायद पहलगाम में लाल चूड़ा पहने नवविवाहिता युवती को उसके पति की लाश पर विलाप करते राजा ने देखा नहीं। हद है, कलमा पढ़ा कर, पुरुषों के अधोवस्त्र उतरवा कर 'तुम हिंदू हो?' पूछा गया। धड़ाधड़ गोलियों से आतंकवादियों ने मानवता को शर्मसार कर दिया। अचानक सैलानियों के घरों में मातम छा गया। रोज तिरंगे में लिपटे फौजियों, पुलिस कर्मचारियों के शव घरों में पहुंच रहे हैं। असहाय प्रजा खून के आंसू रो रही है। राजा कह तो जरूर रहा है हम आतंकवादियों को चुन-चुन कर मारेंगे।

पाकिस्तान को उसके घर में घुस कर मारेंगे परन्तु 1980 से 2025 आ गया न आतंकवादी खत्म हुए, न आतंकवादियों को पनाह और ट्रेड्क्षनग देने वाले और न पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हुआ। जम्मू-कश्मीर में खूनी खेल बंद होना चाहिए। मोदी जी बड़े शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं। क्यों नहीं आतंकवाद का नामो-निशान मिटा देते? लकीरें पीटने से कुछ नहीं बनता। आर-पार की जंग हो जाने दो। राष्ट्र आतंकवाद के आगे नहीं झुक सकता। भारत में एक नया मुस्लिम देश नहीं बन सकता।

खनिज राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त बड़ी कार्रवाई

घुटरा के धुनेठी नदी के किनारे से अवैध ईंट भट्ठे से 50 बोरी कोयला समेत 50000 नग मिट्टी ईंट जब्त किया गया

नागपुर तहसील क्षेत्र के दर्री टोला से 10 टन कोयला समेत 160000 नग मिट्टी ईंट जप्त

अमृतधारा के जंगल से पुलिस विभाग के द्वारा रात्रिकालीन गश्त के दौरान 10 टन कोयला किया जब्त

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। कलेक्टर के निर्देश एवं पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में जिले में कोयले के अवैध परिवहन और उत्खनन पर रोकथाम करने के लिए खनिज राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गठित किया जाकर अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर लगातार क्षेत्र भ्रमण कर कार्यवाही की जा रही है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान खनिज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत घुटरा क्षेत्र से धुनेठी नदी के किनारे राजेश साहू पिता बृजलाल साहू निवासी पिपरटोला घुटरा के द्वारा अवैध ईंट भट्ठे को पकाने के लिए रखे गए लगभग 50 बोरी कोयला को जब्त किया गया है साथ ही साथ 50000 नग ईंट को भी जप्त किया गया है। ग्रामीणों एवं राजस्व विभाग द्वारा बताया गया की भट्ठा संचालक राजेश साहू द्वारा शासकीय ज़मीन मे ईंट निर्माण किया जा रहा है। जिसे जप्त कर खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 तक एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015, के तहत कार्यवाही की गयी है।

इसी क्रम में खनिज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत हरचौका तहसील भरतपुर जिला एमसीबी के खसरा क्रमांक 823 रकबा 5.00 हेक्टेयर पर अवधि 14 अक्टूबर 2024 से 13 अक्टूबर 2029 तक के लिए स्वीकृत खनिज रेत उत्तखनीपट्टा का मौका जाँच किया गया। जिसमें सरपंच एवं सभी ग्रामवासी भी उपस्थित रहे। मौक़े में रेत खदान में खनन कार्य बंद पाया गया। सरपंच एवं ग्रामवासियों द्वारा मजदूरों के द्वारा रेत लोडिंग की बात कही गयी इसके साथ ही साथ मशीन से रेत लोडिंग नहीं करने की सहमति दी गयी। खनिज विभाग द्वारा ग्रामीणों को समझाइश भी दी गयी है कि इससे पंचायत को राजस्व प्राप्ति होंगी। जिससे ग्राम पंचायत का विकास किया जा सकता है। साथ ही साथ ग्रामीणों को यह भी बताया गया की रेत खदान संचालन से जल स्तर में कमी नहीं होंगी, नियमानुसार पर्यावरण स्वीकृति उपरांत ही रेत खदान स्वीकृत किया गया है। इसी क्रम में आज 05 मई 2025 को तहसील नागपुर अंतर्गत ग्राम दर्रीटोला में अंकित राय पिता प्रकाश राय द्वारा अलग-अलग भूस्वामी के लगभग 3 एकड़ ज़मीन में बिना अनुमति के खनिज मिट्टी ईंट का निर्माण किया जा रहा था। मौक़े पर 160000 नग ईंट का निर्माण किया जा चूका है। उक्त ईंट को पकाने के लिए रखे गए लगभग 10 टन कोयला को भी जप्त कर सुरक्षार्थ चौकी नागपुर में रखा गया है। सम्बंधित ईंट भट्ठा संचालक के विरुद्ध खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 तक एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के तहत कार्यवाही की जाएगी। खनिज कोयले के अवैध उत्तखनन स्थल राधारमन, सोनवर्षा क्षेत्रों का भी जाँच किया गया। जिसमे मौक़े पर खनन कार्य बंद पाया गया। राधारमन नगर क्षेत्र कोयले का अवैध उत्तखनन फारेस्ट क्षेत्र के भीतर नाले में किया गया है। मौक़े पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं पाए गये। पुलिस विभाग द्वारा 04 मई 2025 को नागपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत अमृतधारा के जंगलों से रात्रिकालीन गस्त के दौरान भी 10 टन कोयला जप्त किया गया है जिसे सुरक्षार्थ नागपुर पुलिस चौकी में रखा गया है।

ग्राम पंचायत बिछिया टोला तहसील केलहारी में स्वीकृत खनिज रेत उत्तखनीपट्टा जो की सरपंच ग्राम पंचायत बिछिया टोला को खसरा क्रमांक 684 रकबा 4.99 हेक्टेयर क्षेत्र में 17 दिसंबर 2024 से 16 दिसंबर 2029 तक के लिए स्वीकृत है। उक्त रेत खदान का मौका जांच किया गया। जिसमें खदान में रेत लोडिंग का कार्य किया जा रहा था। मौक़े पर ट्रेक्टर के माध्यम से ग्रामीणों के द्वारा ट्रेक्टर ट्रालियो में रेत भराई का कार्य किया जा रहा था साथ ही साथ हर ट्रेक्टर वाहन में प्रत्येक ट्रिप अभिवहन पासबुक भी काटा जाना पाया गया। मौक़े पर ग्राम पंच संतोष गोंड द्वारा अभिवहन पास बुक काटा जा रहा था। मौक़े पर स्वराज सोल्ड वाहन का जाँच किया गया। जिसमे अभिवहन पास क्रमांक 7404415 पाया गया। बता दे की इससे पूर्व में खदान में 11 वाहनों को बिना अभिवहन पास के जप्त किया गया था। जिसमें 55000 अर्थदंड/समझौता की राशि निर्धारित खनिज मद जमा कराया गया है। इस कार्यवाही के दौरान एसडीएम लिंगराज सिदार, एसडीपी एलेक्स टोप्पो, खनिज अधिकारी दयानंद तिग्गा और खनिज निरीक्षक आदित्य मानकर उपस्थित थे।

यदुनंदन सरस्वती बोले- आतंकवाद का सृजन मुसलमानों से हुआ

मीडिया ऑडीटर, बिलासपुर (एजेंसी)। पीठाधीश्वर व वृंदावन धाम के स्वामी यदुनंदन सरस्वती का कहना है कि धर्म गुरुओं को धर्म आधारित राजनीति करनी चाहिए। केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिए राजनीति करना गलत है। उन्होंने शंकराचार्यों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि ज्यादातर शंकराचार्य या तो विवाद में रहे हैं या फिर उस योग्यता को पूरी नहीं करते हैं। ऐसे शंकराचार्यों ने दीक्षा देने की फैक्ट्री खोल रखी है, जो आम लोगों की पहुंच से हमेशा दूर रहते हैं।

छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए यदुनंदन महराज ने बिलासपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आतंकवाद का सृजन मुसलमानों के यहां से हुआ है। जितने भी आतंकवादी हैं, सभी इस्लामी है। इन्हें रोकने के लिए सरकार के पास कठोर कानून है। सरकार को सख्त होना चाहिए और तत्काल निर्णय लेना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अवसरवाद की तलाश में है। बिहार का चुनाव आए तो थोड़ा धूम-धड़ाम कर लेंगे। जिससे उनको हिंदुओं का वोट मिले। जबकि, अभी के हालात में उन्हें प्रतीक्षा नहीं करनी चहिए। देन एंड देयर जवाब देना चाहिए।

वर्तमान समय में मीडिया और सोशल मीडिया के दौर में श्रीमदभागवत कथा को लोगों ने मनोरंजन और आय का साधन बना लिया है। भागवत कहने के लिए भी योग्यता निर्धारित है। 10 साल पहले जो भागवत होता था, तब सुबह तीन से चार और शाम को तीन से चार घंटे प्रवचन होता था। लेकिन, अब केवल तीन से चार घंटे में कथा हो जाती है, उसमें भी संगीत और नाच-गाना में ज्यादा टाइम बीत जाता है। इस तरह के प्रवचन केवल मनोरंजन और आय का साधन बन गया है।

हिंदू धर्म को कभी खतरा नहीं रहा: उन्होंने कहा कि जब तक सृष्टि है तब तक संसार में हिंदू और सनातन रहेगा। हिंदू और सनातन को कहीं कोई खतरा नहीं है। कुछ दुराग्रही, जो छोटे-मोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनसे हमारे धर्म को कहीं कोई खतरा नहीं है। हिंदू राष्ट्र की उठती मांग पर कहा, कैलाश शिखर से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी और कटक के बीच पहले ही यह हिंदू राष्ट्र है, फिर कोई बनाए या ना बनाएं फर्क नहीं पड़ता। साधु-संत हमेशा सनातन धर्म की रक्षा करते हैं और करते रहेंगे।

पीईटी और पीपीएचटी प्रवेश परीक्षाएं 8 मई को दिशा-निर्देश जारी

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा 8 मई 2025 गुरुवार को पीईटी एवं पीपीएचटी (प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। पीईटी परीक्षा प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक और पीपीएचटी परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक जिले के 01 परीक्षा केन्द्र क्रमशः शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़ में आयोजित होना नियत है। अतएव उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किया जाता है। परीक्षा दिवस को प्रत्येक परीक्षार्थी एक घंटे पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र में उपस्थित हो, जिससे उनके मूल पहचान पत्र से उनका पहचान किया जा सकें एवं परीक्षा केन्द्र में जाने हेतु अनुमति दी जा सके। परीक्षार्थी परीक्षा दिवस से एक दिवस पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र की भौगोलिक स्थिति से भली-भाँती परिचित हो जाये। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् किसी भी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परीक्षार्थियों को अपना फोटोयुक्त मूल आई.डी. प्रूफ जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, विद्यालय का फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त अंकसूची मूलरूप में (फोटो कॉपी मान्य नहीं) परीक्षा दिवस में परीक्षा केन्द्र में लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में मोबाइल एवं अन्य डिवाईस ले जाना वर्जित है।

बीमार आवारा एवं असहाय पशुओं के देखभाल हेतु समिति के सदस्यों की बैठक सम्पन्न

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। कलेक्टर के निर्देशानुसार गठित समिति द्वारा शहर के बीनार आवारा एवं असहाय पशुओं हेतु उपचार भोजन व्यवस्था एवं रखरखाव हेतु शेड/पुनर्वास केन्द्र की स्थापना संबंधी चर्चा की गई। जिसमें शहर के विभिन्न वार्डो में कुत्तों एवं अन्य आवारा पशुओं की गिनती कर उन्हें उपयुक्त स्थल देने पर चर्चा की गई, साथ ही कुत्तों की बढ़ती आबादी एवं उनके द्वारा अन्य पशुओं एवं व्यक्तियों को काटने के कारण एवं उपाय के बारे में चर्चा की गई। जिसमें समिति के अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी (रा.) श्री लिंगराज सिदार द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को शहर में बढ़ रही कुत्तों की संख्या को कम करने के लिए उन्हें वार्डवार जहाँ संख्या ज्यादा है । उन्हें पकड़कर नसबंदी कराने एवं उनके रहने के साथ-साथ भोजन संबंधी व्यवस्था करने उपयुक्त स्थल का चुनाव करने के लिए आदेशित किया जाता है, साथ ही पशुधन विकास विभाग के द्वारा पकड़े हुए कुत्तों के टीकाकरण एवं नसबंदी करने की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा सम्बधित एनजीओ के सदस्यों को अन्य पशु प्रेमियों को जोडने एवं रैली निकालकर लोगों को जागरूक करने के लिए समझाईश दी गई। आवारा कुत्तों एवं अन्य पशुओं के भोजन हेतु होटलों से बचे हुए भोजन एवं दान दाताओं से भोजन एकत्रित कर पशुओं को खिलाने की बात कही गई।

उक्त बैठक में पशुधन विकास विभाग से डॉ. विनीत कुमार भारद्वाज, नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ से अमजद एवं जैकू एनिमल रेसक्यू टीम के सदस्य श्रीमति मधू बर्मन, अनीता नियोगी, रानी खनुजा, सुदीप्ता शर्मा एवं प्रज्ञा पाण्डे आदि सदस्यगण उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ में अलग-अलग सड़क हादसों में 7 की मौत

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में हुए अलग-अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई। धमतरी जिले में सड़क हादसों में 3 युवकों ने दम तोड़ दिया। वहीं बलरामपुर जिले के कुसमी में तेज रफ्तार 2 बाइकों के सवार आपस में टकरा गए। हादसे में दोनों बाइक के चालकों की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

कोरबा में 2 ट्रकों की टक्कर के बाद आग लग गई। इस दुर्घटना में एक ट्रक ड्राइवर केबिन में फंसकर जिंदा जल गया, जबकि दूसरा चालक घायल हो गया। तीसरी घटना बालोद की है, जहां जगदलपुर से रायपुर जा रही बस खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में बस कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 12 यात्री घायल हुए हैं।

पहला केस- धमतरी: धमतरी जिले में ग्राम भरदा निवासी टेमन साहू (20) और साहिल साहू दोनों बाइक से जा रहे थे। सोमवार सुबह लगभग 5 बजे मगरलोड में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों दोस्त वहीं गिर गए और बाइक डेढ़ सौ मीटर दूर फेंका गई। जिसमें साहिल उर्फ दीपांशु की मौके पर ही मौत हो गई। टेमन साहू को गंभीर अवस्था में धमतरी जिला अस्पताल लाया गया। यहां से रायपुर ले जाते समय अभनपुर के पास रास्ते में तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, उसे वापस धमतरी लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया ।

दूसरी घटना भखारा थाना क्षेत्र के ग्राम चरौटा की है। ग्राम कुर्रा निवासी वीरेंद्र यादव (19 साल) अपने साथी सोम प्रकाश (19 साल) के साथ लोहारपथरा से वापस लौट रहा था। इसी दौरान चरोटा में अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी। दोनों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया। जहां पर वीरेंद्र यादव की मौत हो गई। सोमप्रकाश का इलाज जारी है।

दूसरा केस, बलरामपुर: बलरामपुर के कुसमी थाना इलाके में 2 बाइक सवार आपस में भिड़ गए। कुसमी-कोरंधा मार्ग में गलफुल्ला नदी के पास रविवार रात 9.30 बजे हादसा हुआ। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में पल्सर बाइक क्रमांक सीजी 30 सी 1168 के चालक फिरोज एराकी (20 साल) और बाइक क्रमांक सीजी 15 सीबी 9498 का चालक सोनू एक्का (21 साल) की मौके पर मौत हो गई। दोनों बाइकों में सवार उनके साथी गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे का कारण तेज रफ्तार बताया जा रहा है। मृतक सोनू एक्का निवासी रातासिली अपने दोस्त मनोज के साथ मेहमानी करने ग्राम करकली शंकरगढ़ गया था। वहां से रात को वापस घर लौट रहा था।दूसरे बाइक में सवार आयान एराकी निवासी डिंडो अपने दोस्त सैफ के साथ कृष्णनगर अपने नाना के घर कसमार आया आया था। वहां से वे बाइक में सवार होकर कुसमी की ओर जा रहे थे। आयान एराकी के साथ बाइक में सवार सैफ को भी गंभीर चोटें आई हैं।

तीसरा केस- कोरबा: कोरबा में सोमवार सुबह 3 बजे दो ट्रकों की टक्कर के बाद आग लग गई। इस दुर्घटना में एक ट्रक ड्राइवर केबिन में फंसकर जिंदा जल गया, जबकि दूसरा चालक घायल हो गया। मृतक चालक की पहचान 30 साल के परमेश्वर मांझी के रूप में हुई। परमेश्वर पथलगांव का निवासी था और कोरबा टीपी नगर से लोड के लिए रानी अटारी जा रहा था। घटना रविवार रात दर्री थाना क्षेत्र में गेरवाघाट पुल के आगे हुई। दर्री थाना पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू कर दी है। दमकल वाहन ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक जल चुका था।

चौथा केस, बालोद: बालोद जिले में नेशनल हाईवे-30 पर सोमवार सुबह जगदलपुर से रायपुर जा रही बस खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में बस कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में करीब 12 यात्री घायल हुए हैं। घायलों का धमतरी में इलाज चल रहा है। घटना रात 3 से 4 बजे के बीच की है। हादसे के समय अधिकतर यात्री सो रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के शीशे टूट गए और यात्री इधर-उधर गिरने लगे। घायलों को धमतरी जिला अस्पताल और क्रिश्चियन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

कलेक्टर ने सुशासन तिहार 2025 के संबंध में ली प्रेस-वार्ता

मुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारी करेंगे शिविरों में शिरकत

योजनाओं का लेंगे फीडबैक

कलेक्टर ने सभी पत्रकारों से समाधान शिविरों के प्रचार प्रसार के लिए किया अपील

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सुशासन तिहार 2025 के संबंध में प्रेस-वार्ता ली। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में सुशासन की स्थापना को लेकर लगातार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शासन-प्रशासन के हर स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता आए, योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन हो और इनका लाभ उन जरूरतमंद वर्गों तक समयबद्ध ढंग से पहुंचे, जिनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी की मंशा के अनुरूप राज्य में सुशासन तिहार-2025 का आयोजन किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता में कलेक्टर ने जिले के सभी पत्रकारों से समाधान शिविरों के ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने की अपील की, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने बताया कि सुशासन तिहार का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान, शासकीय योजनाओं की समीक्षा और निगरानी, विकास कार्यों में तेजी लाना और जनता, जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना है। सुशासन तिहार-2025 का आयोजन तीन चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आयोजित हुआ, जिसमें आम जनता से उनकी समस्याओं और मांगों से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए हैं। आवेदन समाधान पेटी, शिविर और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लिए गए हैं। आवेदन प्राप्त करने के लिए समाधान पेटी की व्यवस्था जिला और विकासखण्ड मुख्यालय स्तर पर की गई थी। उन्होंने बताया कि एमसीबी जिले में कुल 41 हजार 7 सौ तिरसठ आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुल लंबित आवेदन 17,451 हैं, वहीं 24,247 आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है।

कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने कहा कि सुशासन तिहार के दूसरे चरण में प्राप्त आवेदनों को स्कैन कर सॉफ्टवेयर में अपलोड कर संबंधित विभाग जिले के दोनों विधानसभाओं के जनपद और नगरीय निकाय के अधिकारियों को ऑनलाइन व भौतिक रूप से भेजकर उनके गुणवत्तापूर्ण निराकरण की कार्रवाई की जा रही है। मांग से संबंधित आवेदनों को बजट की उपलब्धता के आधार पर निराकृत किया जा रहा है। आवेदनों के निराकरण की गुणवत्ता की समीक्षा जिला और राज्य स्तर पर की जा रही है। तीसरे एवं अंतिम चरण की शुरुआत 05 मई 2025 से हो रही है, जो 30 मई 2025 तक चलेगी। इस दौरान जिले के 8 से 15 ग्राम पंचायतों के बीच एक समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। नगरीय निकायों में भी शिविर लगाए जाएंगे। जिले में कुल 21 समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे।

जिले के दोनों विधानसभा के इन पंचायतों में होगा समाधान शिविर

जिसमें भरतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत कोटाडोल, कुंवारपुर, देवगढ़, कंजिया, भगवानपुर, माड़ीसरई, मैनपुर, रामगढ़ और सेमरिहा में समाधान शिविर होगा। वहीं खड़गवां विकासखंड के ग्राम पंचायत शिवपुर, रतनपुर, जरौंधा, दुबछोला, कोड़ा और आमाडांड में होगा। इसके साथ ही मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के केल्हारी, पाराडोल, नागपुर, कछौड़, कठौतिया और पेंड्री में समाधान शिविर संपन्न होगा।

इन शिविरों में आवेदकों को उनके आवेदनों पर की गई विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। शिविरों में आवेदन भी लिए जाएंगे। विभागीय अधिकारी समाधान शिविरों में विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी देंगे। साथ ही हितग्राही मूलक योजनाओं के आवेदन पत्र व प्रपत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे। समाधान शिविरों में विकासखंड एवं अनुभाग स्तर के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जिला स्तर से भी कुछ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इसी तरह की व्यवस्था नगरीय निकायों के शिविरों में भी रहेगी।

कलेक्टर ने कहा कि सुशासन तिहार के तीसरे चरण के दौरान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री गण, मंत्रीगण, मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी कुछ समाधान शिविरों में शामिल होंगे और आम जनता से सीधा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री विकास कार्यों और योजनाओं का औचक निरीक्षण भी करेंगे और योजनाओं के जमीनी लाभ के बारे में फीडबैक लेंगे। मुख्यमंत्री जिला मुख्यालय पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे, जिसमें शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति, विभिन्न योजनाओं की प्रगति और आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री अपने प्रवास के दौरान प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और विभिन्न संगठनों एवं नागरिकों से भेंट भी करेंगे।

कलेक्टर ने पत्रकार साथियों से सुशासन तिहार 2025 अंतर्गत आयोजित समाधान शिविरों के प्रचार-प्रसार में सहभागी बनने की अपील की, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले सकें। इस अवसर पर सुशासन तिहार 2025 के लिए नियुक्त जिला स्तरीय नोडल अधिकारी व जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ अपर कलेक्टर अनिल सिदार एवं मीडिया के विभिन्न प्रतिनिधि उपस्थित थे।

पहलगाम हमला, हिमांशी नरवाल का महिला आयोग-ओवैसी ने बचाव किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी का मुस्लिम और कश्मीरी लोगों पर दिए बयान पर विवाद हो रहा है। 1 मई को हिमांशी ने कहा था- घटना के बाद लोग जिस तरह से मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ बोल रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। हमें न्याय चाहिए। जिन लोगों ने गलत किया उनको सजा मिलनी चाहिए। बयान के बाद हिमांशी की ट्रोलिंग की गई। लोगों ने उन्हें अपशब्द भी कहे। उन्हें गोली मारने की भी बात कही गई। सोमवार को हिमांशी के सपोर्ट में राष्ट्रीय महिला आयोग आया और चीफ असदुद्दीन ओवैसी आए। आयोग ने कहा- किसी महिला को उसकी अभिव्यक्ति के आधार पर ट्रोल करना गलत है। हिमांशी को उनके एक बयान के लिए ट्रोल करना गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी महिला के निजी जीवन को आधार बनाकर उसे ट्रोल करना अस्वीकार्य है। ओवैसी ने भी किया हिमांशी का समर्थन हिमांशी को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सोशल मीडिया पर हजारों अन्य लोगों से समर्थन भी मिला है। ओवैसी ने सरकार से कुछ राज्यों में कश्मीरियों को निशाना बनाए जाने की खबरों के बीच हिमांशी के शब्दों को याद रखने के लिए कहा।

कुलगाम में युवक का शव मिला

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में रविवार को एक 22 साल के एक युवक का शव पहाड़ी नाले में पाया गया। युवक की पहचान इम्तियाज अहमद माग्रे के रूप में हुई है। इम्तियाज का शव रविवार सुबह जिले के अहरबल इलाके में अदबल नाले से निकाला गया था। परिवार का आरोप है कि सुरक्षा बल मृतक को पहलगाम हमले से जुड़ी पूछताछ के लिए ले गए थे। वहीं, पुलिस ने बताया कि इम्तियाज ने आतंकवादियों का ओवर ग्राउंड वर्कर होने की बात कबूल की थी। वह 23 अप्रैल को हुई मुठभेड़ से भी जुड़ा था। उस दिन दो आतंकवादी भाग निकले थे। उसने लश्कर के ठिकाने की जानकारी होने की बात भी कबूल की थी। इसके बाद उसे जंगल में उसकी बताई जगह ले जाया जा रहा था। इसी दौरान वह भागने के लिए नदी में कूद गया। पुलिस ने पूरी घटना के ड्रोन फुटेज जारी किए है जिसमें इम्तियाज नाले में कूदते और बहते दिख रहा है। मामले में केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट मंत्री सकीना इटू ने घटना की ज्यूडीशियल इन्क्वायरी की मांग की।

कानपुर में जिंदा जलीं पति-पत्नी और 3 बेटियां

कानपुर (एजेंसी)। कानपुर में रविवार रात 8 बजे एक 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। हादसे में एक परिवार के 5 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में पति-पत्नी और उनकी 3 बेटियां हैं। बिल्डिंग के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर जूता-चप्पल बनाने का कारखाना था। ऊपर के 4 फ्लोर में दो भाइयों का परिवार रहता था। आग की शुरुआत ग्राउंड फ्लोर पर कारखाने से हुई। देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से अनुबंध के बाद हुई कार्रवाई की समीक्षा

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना हमारा संकल्प है। इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की डेयरी क्षेत्र में विशेषज्ञता का लाभ संपूर्ण प्रदेश को समान रूप से मिले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। सहकारी संघों के साथ निजी डेयरी संचालकों को भी आवश्यक कंसल्टेंसी उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए अन्य राज्यों की बेहतर नस्ल की गाय-भैंसों

को प्रदेश में लाने और उन्हें किसानों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने की आवश्यकता है।

यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि प्रदेश में उत्पादित दूध के वैल्यू एडिशन के बाद ही डेयरी उत्पाद प्रदेश के बाहर जाएं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और म.प्र. राज्य सहकारी दुग्ध संघ के मध्य संपादित अनुबंध के बाद की गई कार्रवाई की समत्व भवन में समीक्षा कर रहे थे। बैठक में पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लखन पटेल, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रमुख श्री मिनेश शाह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री एस. रघुपति, महाप्रबंधक श्री संजय गोबानी सहित अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में बड़ी गौशालाएं विकसित की जा रही हैं। इनके विकास और बेहतर प्रबंधन से भी दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालय भी डेयरी टेक्नोलॉजी और एनिमल हसबेंडरी संबंधी कोर्स संचालित करें।

कई राज्यों में 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल

पहलगाम/नई दिल्ली (एजेंसी)। पंजाब में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ठाकुरपुर गांव में क्क्स्त्र ने पाकिस्तानी नागरिक को अरेस्ट किया है। आरोपी से पास आईडी कार्ड भी मिला है। जिस पर उसकी पहचान हुसनैन लिखी है और वह गुज्जरांवाला का रहने वाला है। इस मॉक ड्रिल का मकसद लोगों को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार करना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की। वहीं पिछले दिनों वे एयरचीफ मार्शल एपी सिंह और नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी से भी मिल चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वायुसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री मोदी को युद्ध की तैयारियों पर जानकारी दी। रविवार की इस मीटिंग में बताया कि एयर फोर्स हर हालात से निपटने को तैयार है। पश्चिमी सीमा पर डिफेंस नेटवर्क भी पूरी तरह एक्टिव है और राफेल भी तैयार हैं। इधर, भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी नागरिक को अरेस्ट किया है। आरोपी की गिरफ्तारी गांव ठाकुरपुर के पास सीमा पर हुई। आरोपी से पास आईडी कार्ड भी मिला है। जिस पर उसकी पहचान हुसनैन लिखी है और वह गुज्जरांवाला का रहने वाला है। उधर पाकिस्तान ने सोमवार को एक और मिसाइल का टेस्ट किया। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है।

देहरादून में बादल फटने से सांग नदी में बाढ़

नई दिल्ली (एजेंसी)। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश सहित देश के 26 राज्यों में आंधी-तूफान के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की है। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी में यलो अलर्ट जारी किया गया है।

आईएमडी ने यूपी-बिहार में ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की है। वहीं, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश होगी, लेकिन अधिकतम तापमान में और ज्यादा गिरावट होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक, सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में 7-8 मई तक मौसम ऐसा ही बना रहने का अनुमान है। उधर, जयपुर में रविवार को बिजली गिरने से 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। सीकर में तेज बारिश के चलते जलभराव हुआ। क्क के 10 जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। मध्य प्रदेश में आंधी-तूफान के साथ तेज

बारिश हुई, छतरपुर में एक मोबाइल टावर गिर गया। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास और खंडवा में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। इधर, उत्तराखंड के देहरादून में बादल फटने से सांग नदी में बाढ़ आ गई। इस दौरान कई टूरिस्ट फंस गए। हालांकि, सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया।

जज कैश केस-कमेटी ने सीजेआई को जांच रिपोर्ट सौंपी

नई दिल्ली (एजेंसी)। कैश मामले में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच रिपोर्ट सीजेआईसंजीव खन्ना को सौंपी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रेस रिलीज के जरिए इसकी जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 3 मई को जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई। 4 मई को ये रिपोर्ट सीजेआई को दी गई है। अब इस मामले में आगे का फैसला सीजेआई लेंगे। जांच कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अनु शिवरामन

शामिल हैं। जस्टिस वर्मा तब विवादों में घिर गए थे, जब उनके लुटियंस दिल्ली स्थित घर में 14 मार्च की रात आग लगी थी। उनके घर के स्टोर रूम से 500-500 रुपए के जले नोटों के बंडलों से भरे बोरे मिले थे।

सीजेआई खन्ना के आदेश पर 21 मार्च को मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई थी।24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा का दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर की सिफारिश की।

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 15 मई को सुनवाई

दिल्ली (एजेंसी)। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई 15 मई को होगी। इससे पहले 17 अप्रैल को कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया था। साथ ही अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का जवाब आने तक वक्फ घोषित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा था। केंद्र ने 25 अप्रैल को दायर हलफनामे में कहा कि कानून पूरी तरह संवैधानिक है। यह संसद से पास हुआ है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। 1332 पन्नों के हलफनामे में सरकार ने दावा किया 2013 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ। इस वजह से कई बार निजी और सरकारी जमीनों पर विवाद हुआ। वहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के आंकड़ों को गलत बताया और कोर्ट से झूठा हलफनामा देने वाले वाले अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की।

नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 70 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई हैं, लेकिन कोर्ट सिर्फ पांच मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगा। इसमें सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका शामिल है।

हिंसा के 25 वें दिन ममता का मुर्शिदाबाद दौरा

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंसा के 25वें दिन मुर्शिदाबाद पहुंची। उन्होंने कहा कि यहां अब हालात पूरी तरह सामान्य हो चुके हैं। सीएम ने हिंसा प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का ऐलान किया। मनाता ने बताया कि उन्हें राज्यपाल सीवी आनंद बोस की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग दंगे भड़काते हैं, उन्हें बंगाल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मुख्यमंत्री ने

बीएसएफ पर भी सवाल उठाए और कहा कि अगर फायरिंग नहीं होती, तो अगले दिन हिंसा नहीं भड़कती ममता ने बताया कि वह आज ही बहरमपुर में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगी। कल धुलियन जाएंगी।यहां हिंसा से प्रभावित लोगों को मुआवजा देंगी, जिनके घर और दुकानें जला दी गई थीं। बंगाल गवर्नर ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी पश्चिम बंगाल के गवर्नर सी. वी. आनंद बोस ने रविवार को मुर्शिदाबाद दंगे पर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें कट्टरपंथ और उग्रवाद को पश्चिम बंगाल के लिए बड़ा खतरा बताया गया। गवर्नर ने कहा कि बंगाल को दोहरा खतरा है, जो खास तौर पर बांग्लादेश से सटे मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में ज्यादा है, क्योंकि यहां हिंदू आबादी अल्पसंख्यक हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज की

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर रिट याचिका खारिज कर दी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए दुबे पर अवमानना कार्यवाही की मांग की गई थी।

सीजेआई ने कहा- हमारे कंधे मजबूत हैं, हम याचिका पर विचार नहीं करना चाहते हैं। बेंच ने याचिकाकर्ता विशाल तिवारी की दलीलों पर कहा- हम फिलहाल कोई दलील या बहस नहीं सुनना चाहते, लेकिन हम एक शॉर्ट ऑर्डर पास करेंगे। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह अदालत और जजों की गरिमा का सवाल है। याचिका में विशाल तिवारी ने निशिकांत दुबे के बयान को कोर्ट के लिए अपमानजनक और निंदनीय बताया था। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर एक्शन लेने की समय सीमा 3 महीने तय की थी।

वित्त-मंत्री ने एशियन बैंक से पाकिस्तान की मदद रोकने कहा

नई दिल्ली (एजेंसी)। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान की इंटरनेशनल फंडिंग रोकने की रणनीति बना रहा है। इसके लिए सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख से मुलाकात की है। वित्त मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्मला सीतारमण ने ्रक्ष्क के डायरेक्टर मसाटो कांडा से मुलाकात में पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद घटाने की मांग की है। इसके साथ ही निर्मला ने इटली के वित्त मंत्री से मुलाकात जियानकार्लो जियोर्जेटी से पाकिस्तान के फंड रोकने पर चर्चा की है। सीतारमण एशियन इटली के मलान में चल रहे एशियन डेवलपमेंट बैंक के 58वे एनुअल मीट में शामिल होने पहुंची हैं। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में भेजने के लिए भारत यूरोपीय देशों के साथ मुलाकात कर रहा है।

अमृतसर में आतंकी नेटवर्क से जुड़े 3 गिरफ्तार

अमृतसर (एजेंसी)। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय गिरोह नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्रिटेन स्थित गिरोह के गुर्गों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने गैंगस्टर धर्मप्रीत सिंह उर्फ ??धर्म संधू और जस्सा पट्टी के नेटवर्क से जुड़े तीन साथियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान विजय मसीह, अग्रेज सिंह और इकबाल सिंह के रूप में हुई है।

डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी तरनतारन जिले के हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये तीनों आरोपी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गिरोह से जुड़े हुए थे और हथियारों की तस्करी में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। आरोपियों से 4 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। जिनकी फोरेंसिक जांच चल रही है। इससे इस पूरे गिरोह के पिछले और अगले लिंक का पता चलेगा।

इस संबंध में थाना लोपोके में मामला दर्ज किया गया है और पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच जारी है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ से इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की और कड़ियां उजागर होंगी। पुलिस ने इसे आतंक और हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी रणनीतिक सफलता बताया है।

महाकाल मंदिर परिसर में लगी आग, उज्जैन में दूर से दिखाई दी लपटें

उज्जैन (एजेंसी)। उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में कंट्रोल रूम की छत पर आग लग गई। इससे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बैटरियां जल गईं। दूर से ही धुआं और आग की लपटें दिखाई दे रही थी। आग लगने के बाद मंदिर में भक्तों का प्रवेश रोकना पड़ा। आग बुझाने के दौरान एक कर्मचारी के दोनों हाथ झुलस गए। घटना

मंदिर के गेट नंबर 1 पर स्थित अवंतिका गेट के कंट्रोल रूम की छत पर हुई। सूचना मिलते ही दमकलें मौके पर पहुंची।

कुछ ही देर बाद ही आग पर काबू पा लिया गया। इसके बाद मंदिर के गेट को दोबारा खोल दिया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने की सूचना मिलते ही कलेक्टर रोशन सिंह, महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक, उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा, नगर निगम कमिश्नर आशीष पाठक सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट्स में पेंडिंग केसों की जानकारी मांगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देशभर के सभी हाईकोर्ट्स से पेंडिंग केसों की जानकारी मांगी। कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट उन केसों की रिपोर्ट जमा करें, जिनमें 31 जनवरी 2025 से पहले फैसला सुरक्षित रखा गया, लेकिन आज तक सुनाया नहीं गया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने कहा- केसों की सुनवाई में होने वाली इस तरह की देरी बेहद परेशान करने वाली है। वक्त पर न्याय मिले। इसके लिए हमें कुछ जरूरी दिशा-निर्देश तय करने होंगे। ऐसा चलता नहीं रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। इसमें चार दोषियों ने शिकायत की थी कि उनकी आपराधिक अपीलों पर झारखंड हाईकोर्ट ने 2022 में फैसला सुरक्षित किया था, लेकिन अब तक फाइनल सुनवाई नहीं हुई। झारखंड हाईकोर्ट ने हफ्तेभर में 75 केस पर फैसला सुनाया याचिकाकर्ताओं के वकील फौजिया शकील ने बताया- वर्तमान केस में सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने कई मामलों में सुनवाई पूरी की है। हालांकि याचिकाकर्ताओं की अपील पर अब भी फैसला आना बाकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा- नोटिस जारी होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने एक हफ्ते में 75 आपराधिक मामलों पर सुनवाई पूरी की। इसके बाद बेंच ने झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि उन 75 अपीलों की लिस्ट प्रस्तुत करें जिन पर हाल ही में निर्णय हुआ है। यह भी बताएं कि इन मामलों में फैसला कब सुरक्षित किया गया था। जानिए क्या है पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट हत्या और रेप के एक मामले में सुनवाई कर रहा था, जिसमें चार मुख्य में से तीन पर हत्या और एक पर रेप का आरोप है। आरोपी अनुसूचित जनजाति और ओबीसी से आते हैं। इन्होंने 2022 में अपनी सजा के खिलाफ आपराधिक अपीलें झारखंड हाईकोर्ट में दायर की थीं। लेकिन करीब 2-3 साल बीतने के बावजूद उन पर फैसला नहीं आया।

राहुल की नागरिकता इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रिपोर्ट के अभाव में केस किया बंद

लखनऊ (एजेंसी)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताने वाले केस को बंद कर दिया है। कोर्ट ने कहा- राहुल की नागरिकता की रिपोर्ट केंद्र सरकार पेश नहीं कर पाई। कोर्ट ने कहा- केवल रिपोर्ट के इंतजार में याचिका को लंबित नहीं रखा जा सकता। जब भी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्राप्त होती है, तो याचिकाकर्ता को उसकी एक प्रति उपलब्ध कराएं और उसे कोर्ट में भी प्रस्तुत करें। केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि यह मामला दो देशों के बीच की संवेदनशील जानकारी से जुड़ा है। संबंधित देश को कई रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है, इसलिए कुछ और समय दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस याचिका की सुनवाई पूरी की जा रही है। याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता

है कि वह नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य फोरम या कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। 21 अप्रैल को हुई सुनवाई में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडेय ने केंद्र की ओर से स्थिति रिपोर्ट पेश की, लेकिन कोर्ट ने उसे अपर्याप्त मानते हुए सख्त टिप्पणी की- यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है, देरी नहीं चलेगी। कोर्ट ने केंद्र से पूछा, राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं?

10 दिन में स्पष्ट कीजिए। हैरानी की बात यह रही कि राहुल गांधी की ओर से कोई वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। कर्नाटक के रहने वाले विग्नेश शिशिर ने याचिका दायर कर दावा किया है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की एक कंपनी में डायरेक्टर रहते हुए खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि दोहरी नागरिकता रखने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है।

विग्नेश शिशिर ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की थी।

इससे पहले लखनऊ हाईकोर्ट ने 24 मार्च को इस केस की सुनवाई की थी। जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। सरकार ने 8 सप्ताह का समय मांगा था। इस पर 21 अप्रैल सुनवाई की तारीख तय हुई थी।

19 दिसंबर, 2024 को जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (्रस्त्र) सूर्यभान पांडेय को केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया था। गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट में बताया था कि उन्होंने यूके सरकार को लेटर लिखा है। यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से पेश वकील ने कहा- समय दिया जाए। पूरे मामले में क्या जांच हो रही है। इसकी पूरी रिपोर्ट 8 सप्ताह में तैयार करके पेश करेंगे।

डोप टेस्ट में पॉजिटीव पाये जाने के कारण खेल से दूर हुए रबाडा

जोहान्सबर्ग (एजेंसी)। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। डोप टेस्ट में पॉजिटीव पाए जाने के बाद से ही वह निलंबन झेल रहे हैं। इसी कारण उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) भी छोड़ना पड़ा है। रबाडा आईपीएल में गुजरात टाइटन्स की ओर से खेल रहे थे। रबाडा पिछले माह अचानक ही स्वदेश लौट गये थे हालांकि उन्होंने तब कोई कारण नहीं बताया था। वहीं क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसके) ने कहा है कि रबाडा को निलंबित कर दिया गया है। रबाडा के ऊपर प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन का आरोप था। । वहीं रबाडा ने कहा कि वह खेल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाये रखेंगे। साथ ही कहा कि देश की ओर से खेलने का उनका जुनून बना हुआ है। दूसरी ओर बोर्ड ने कहा, सीएसए पूरी तरह से डोप मुक्त खेल के लिए प्रतिबद्ध है और पेशेवर और शौकिया दोनों तरह के क्रिकेट खिलाड़ियों को सभी नियमों का पालन करना ही होगा। साथ ही कहा कि सभी खिलाड़ियों को इस मामले में बचाव का अवसर भी दिया जाएगा। रबाडा ने यह भी कहा कि वह क्रिकेट में वापसी के लिए उत्साहित हैं और उन्होंने अपने परिवार, कानूनी टीम और गुजरात टाइटन्स के प्रति आभार जताया है। वहीं माना जा रहा है कि रबाडा का निलंबन कुछ समय का ही रहेगा।

ओवेन के शामिल होने से पंजाब किंग्स को मिलेगा लाभ

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईपीएल में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में उतरी पंजाब किंग्स भी प्लेऑफ की दावेदार बनी हुई है। उसने अब चोटिल ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की जगह पर एक अच्छे ऑलराउंडर मिच ओवेन को जगह दी है जिसका लाभ उसे मिलेगा। इसका कारण है कि वह अच्छे बल्लेबाज और गेंदबाज हैं। वहीं मैक्सवेल इस सत्र में असफल रहे हैं ऐसे में उनके बाहर होने से टीम को शायद ही कोई मुश्किल हो। ओवेन के आने से पंजाब किंग्स की प्लेऑफ की उम्मीदें बढ़ेंगी। पंजाब किंग्स की टीम आईपीएल अंक तालिक में अभी चौथे नंबर पर है और वह प्लेऑफ में पहुंचने के लिए पूरी ताकत लगा रही है।ओवेन तस्मानिया के रहने वाले हैं। उन्हें टी20 क्रिकेट का अच्छा अनुभव है। उन्होंने 34 टी20 मैच खेले हैं। उन्होंने 646 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक भी शामिल हैं। उनके आने से पंजाब किंग्स की टीम को एक अच्छा बल्लेबाज ओर गेंदबाज मिलेगा। ओवेन ने टी20 में सबसे ज्यादा 108 रन बनाए हैं। इससे पता चलता है कि वे बड़े शॉट लगा सकते हैं। उन्होंने 10 विकेट भी लिए हैं।

इससे पता चलता है कि वे गेंदबाजी भी अच्छी कर लेते हैं। ओवेन को आईपीएल के नियमों के अनुसार टीम में शामिल किया गया है। मैक्सवेल के लिए यह आईपीएल सीजन अच्छा नहीं रहा। वह 6 मैचों में केवल 48 रन बनाए। उनका सबसे ज्यादा स्कोर 30 रन था। उन्होंने 97.96 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए।

प्लेऑफ में पहुंचने की दौड़ में सबसे आगे रहती है आरसीबी, मुम्बई

मुम्बई (एजेंसी)। आईपीएल के 18 सत्र में अब प्लेऑफ में जगह बनाने की होड़ जारी है। इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) भी शामिल है जो पिछले 5 आईपीएल सत्र में से सबसे अधिक 4 बार टीम प्लेऑफ में पहुंची है हालांकि वह एक बर भी खिताब नहीं जीती है। इस बार टीम अंक तालिका में पहले नंबर पर है और उसका प्लेऑफ में पहुंचना तय है। वहीं पांच बार खिताब जीतने वाली मुम्बई इंडियंस भी खराब शुरुआत से उबरकर दौड़ में बनी हुई है। वहीं गत चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) भी पिछले 5 स्त्र में दो ही बार प्लेऑफ में पहुंची है। उनके अलावा दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स ने भी 2-2 बार प्लेऑफ में पहुंची है।

आठ टीमें ऐसी हैं जिन्होंने दो-दो बार खिताब जीता है, वहीं एकमात्र टीम ऐसी है जिसने इस दौरान 4 बार प्लेऑफ में कदम रखा है पर खिताब नहीं जीत पायी। मुंबई इंडियंस पिछले पांच सत्र में केवल 2 ही बार नॉकआउट में पहुंचने में सफल रही है। टीम 2020 में अंतिम बार खिताब जीती थी। वहीं पांच बार की विजेता और 2008 से 2019 के बीच लगातार 10 साल नॉकआउट में पहुंचने वाली सीएसके इस बार पहले ही बाहर हो गयी है। सीएसके साल 2020 से केवल दो ही बार प्लेऑफ तक पहुंचने में सफल रही है।

इंग्लैंड दौरे पर कुलदीप यादव होंगे बेहद अहम खिलाड़ी, एक्सपर्ट्स ने बताया गेंदबाज को घातक

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के पूर्व चयनकर्ताओं और कोचों का मानना है कि, कुलदीप यादव एक ऐसे मैच विजेता खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड के खिलाफ उसकी धरती पर होने वाली टेस्ट सीरीज में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कलाई के इस स्पिनर को बल्लेबाजी ऑलराउंडरों पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कुलदीप को एक्स फैक्टर बताया है। उनका मानना है कि रविंद्र जडेजा अपने बेहतर बल्लेबाजी कौशल के कारण पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए पहली पंसद होंगे। लेकिन कुलदीप के टीम में शामिल होने से भारत का स्पिन विभाग और मजबूत होगा।

राष्ट्रीय चयन समिति आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीमों की स्थिति स्पष्ट हो जाने के बाद इंग्लैंड दौरे के लिए भारत और ए टीम की घोषणा कर सकती है। प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाने वाली अन्य 6 टीमों में शामिल लाल गेंद के विशेषज्ञ खिलाड़ी जल्दी इंग्लैंड के दौरे पर चले जाएंगे जैसा कि पहले भी होता रहा है। इससे उन्हें वहां की परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया

में वाशिंगटन सुंदर ने पहली पसंद के स्पिनर के रूप में शुरुआत की। वजह, न्यूज़ीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर खराब प्रदर्शन के बाद जडेजा और रविचंद्रन अश्विन दोनों को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया था। अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच में ही संन्यास ले लिया था जबकि वॉशिंगटन सुदंर तीन टेस्ट मैच में केवल तीन विकेट ही ले पाए थे।

वहीं इस कड़ी में चयन समिति के पूर्व अध्यक्ष एमएसके प्रसाद, उनकी चयन समिति के सहयोगी देवांग गांधी और भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और प्रसिद्ध कोच डब्ल्यूवी रमन सभी को लगता है कि कुलदीप के पास वह एक्स फैक्टर है जिसकी भारत को इंग्लैंड में जरूरत पड़ेगी। खेल के सबसे चतुर विश्लेषकों में से एक रमन ने कहा कि कुलदीप यादव एक आक्रामक विकल्प हैं और उन्हें इंग्लैंड में भारतीय टीम में होना चाहिए। उन्होंने अब तक 12 टेस्ट खेले हैं और अगर हम उनके स्ट्राइक रेट पर गौर करें तो वह हर 6 ओवर में एक विकेट है। इसलिए जडेजा के साथ कुलदीप को टीम में रखना मेरे लिए सबसे आसान काम होगा।

पूर्व चयनकर्ता प्रसाद व देवांग बोले, इंग्लैंड दौर में कुलदीप निभा सकते हैं अहम भूमिका

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्व चयनकर्ताओं एमएस के प्रसाद और देवांग गांधी का मानना है कि चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव अगले माह होने वाले इंग्लैंड दौर में एक्स फैक्टर साबित हो सकते है। इन पूर्व चयनकर्ताओं के अनुसार अनुसार कुलदीप एक मैच विजेता खिलाड़ी हैं और टेस्ट सीरीज में उनका सामना करना इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगा। इसलिए उन्हें ऑराउंडरों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिये। उनका मानना है कि ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए पहली पसंद होंगे पर साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि कुलदीप के टीम में शामिल होने से भारत की स्पिन गेंदबाजी बेहतर होगी।

माना जा रहा है कि कुछ समय बाद इंग्लैंड दौरे के लिए भारत और ए टीम की घोषणा हो सकती है। इसका कारण ये है कि आईपीएल प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाने वाली टीमों में शामिल लाल गेंद के खिलाड़ी जल्दी इंग्लैंड के दौरे पर चले जाएंगे जिससे कि इससे उन्हें वहां के हालातों से तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया में वाशिंगटन सुंदर पहली पसंद के स्पिनर के रूप में उभरे। इसकी वजह, न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू

मैदान पर खराब प्रदर्शन के बाद जडेजा और अनुभवी आर अश्विन दोनों को अंतिम एकादश में शामिल नहीं किया गया था। अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच में ही संन्यास ले लिया था, जबकि वॉशिंगटन तीन टेस्ट मैच में केवल तीन विकेट हासिल कर पाए थे।

चयन समिति के पूर्व अध्यक्ष एमएसके प्रसाद, उनकी चयन समिति के सहयोगी देवांग गांधी और भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और कोच रहे डब्ल्यूवी रमन सभी को लगता है कि कुलदीप के पास वह 'एक्स फैक्टर' है जिसकी भारत को इंग्लैंड में जरूरत पड़ेगी। रमन ने कहाकि कुलदीप यादव एक आक्रामक विकल्प हैं और उन्हें इंग्लैंड में भारतीय टीम में होना चाहिए। उन्होंने अब तक 12 टेस्ट खेले हैं और अगर हम उनके स्ट्राइक रेट पर गौर करें तो वह हर छह ओवर में एक विकेट (37.3 गेंद प्रति विकेट) है। इसलिए जडेजा के साथ कुलदीप को टीम में रखना मेरे लिए सबसे आसान काम होगा।

प्रसाद को भी लगता है कि वह वॉशिंगटन की तुलना में कुलदीप बेहतर विकल्प हो सकते हैं। प्रसाद ने कहाकि हालांकि आप अब भी वॉशिंगटन को टीम में रख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कुलदीप जैसे मैच विजेता स्पिनर की जरूरत है। उन्होंने कहाकि कुलदीप एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच जीतने की क्षमता रखते हैं। इंग्लैंड में कई ऐसी जगह है जहां स्पिनर को मदद मिलती है और वहां की परिस्थितियों में कलाई का स्पिनर होने के कारण कुलदीप बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं।

केकेआर के खिलाफ 1 रन से मुकाबला गंवाने के बाद टूटे रियान पराग

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक रन से मिली हार के लिए खुद को दोषी बताया है। ईडन गार्डन्स में खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद चार विकेट पर 206 रन बनाए। इसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग के 95 रनों के बावजूद 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 205 रन ही बना सकी।

रियान पराग ने मैच के बाद कहा कि, मैं मेरे आउट होने से बस दुखी था। मैं आखिरी ओवर तक रुकने की प्लानिंग बना रहा था। हम 16वें और 17वें ओवर में ज्यादा नहीं बना सके। मेरी तरफ से गलत कैलकुलेशन थी। हमें खत्म करना चाहिए था। मुझे लगता है कि हमें शुरुआती 6 ओवर में अच्छे विकल्प तलाशने होंगे। स्पिनर ने अच्छा किया। हम गेंद से कुछ रन कम करने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन खेल हमारे हाथ में था, हमें इसे खत्म कर देना चाहिए था।

पराग ने आगे कहा कि, मैं नहीं चाहता कि गेंदबाज लगातार गेंदबाजी करे। माधवाल सिर्फ अपना दूसरा गेम खेल रहे थे। अब ऐसा लगता है कि हम कुछ और कर सकते थे। लेकिन शायद ये सही निर्णय था, मुझे नहीं पता। बहुत मुश्किल आंद्रे रसेल आए और अपना समय लिया और फिर अच्छी तरह से गति पकड़ी। ये देखना बहुत अच्छा था। मुझे यहां ये इंटरव्यू देते हुए बहुत बुरा लग रहा है लेकिन खेल ऐसा ही है।

आईपीएल में अश्विन सहित ये पांच खिलाड़ी फ्लाप साबित हो रहे

मुम्बई (एजेंसी)। आईपीएल के इस सत्र में करोड़ों की राशि पाने के बाद भी पांच खिलाड़ी असफल रहे हैं और अपनी टीम की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं जबकि नीलामी में इन खिलाड़ियों को मोटी रकम मिली थी। वहीं अब टूर्नामेंट के आधे से अधिक मैच निकल गये हैं पर इन खिलाड़ियों ने लय नहीं हासिल की है। ऐसे में इन्हें खरीदने वाली टीमों को खासा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है क्योंकि ये टीम पर बोझ बनने जा रहे हैं। इनकी टीमों को ने जब इन खिलाड़ियों को खरीदा था तो उन्हें काफी उम्मीदें थीं जिनपर अब पानी फिरता दिख रहा है। इस खिलाड़ियों का प्रदर्शन औसत से भी कम रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अनुभवी रविचंद्रन अश्विन को नीलामी में 9.75 करोड़ रुपये में खरीदा पर वह भी असफल रहे। अश्विन को इससे पहले 7.6 करोड़ तक का वेतन मिला था पर इस बार सीएसके ने उन्हें ज्यादा रकम दी थी पर उन्होंनें निराश किया। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के उपकप्तान वेंकटेश अय्यर भी इस बार विफल रहे हैं। वेंकटेश को पिछले प्रदर्शन के आधार पर केकेआर ने 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा था पर वह फ्लॉप रहे हैं। टीम प्रबंधन उन्हें कप्तानी विकल्प के तौर पर देख रहा था पर वेंकटेश ने टीम को बल्लेबाज और गेंदबाजी दोने में ही निराश किया।राजस्थान रॉयल्स ने युवा विकेटीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को 14 करोड़ रुपये में बरकरार रखा पर जुरेल अपने को साबित नहीं कर पाये और लगातार नाकाम रहे हैं जबकि उन्हें फिनिशर की भूमिका निभानी थी।दिल्ली कैपिटल्स ने युवा गेंदबाज मुकेश कुमार में 8 करोड़ रुपये में खरीदा जबकि पिछले सीजन में उनका इकोनॉमी रेट 10.37 था। इस सीजन में भी उन्होंने 10 की इकोनॉमी से रन दिये हैं जिससे उनको खरीदेने का फैसला भी सही साबित नहीं हुआ है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने युवा गेंदबाज आकाश दीप को 8 करोड़ रुपये में खरीदा। उन्होंने 8 मैच खेले और 7 विकेट लिए वह भी 11 से ज्यादा की इकोनॉमी रेट से रन दिये हैं। इस सीजन भी उन्होंने अब तक 4 मैच खेले हैं और 12 की इकोनॉमी से रन दिए हैं। उसे में उन्हें लेने का फैसला गलत साबित होता दिख रहा है।

रन लेते समय बल्लेबाज की जेब से गिरा मोबाइल फोन, छिड़ गया नया विवाद

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंग्लैंड में काउंटी चैंपियनशिप मैच के दौरान एक विचित्र दृश्य देखने को मिला, जब एक बल्लेबाज गलती से मैदान में मोबाइल फोन ले आया और डबल रन लेने के प्रयास में मोबाइल फोन उसकी जेब से फिसल गया। काउंटी चैंपियनशिप के चौथे राउंड के दूसरे दिन के खेल में, लंकाशायर के गेंदबाज टॉम बेली ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर ग्लूस्टरशायर के खिलाफ अपनी टीम के पहले इनिंग स्कोर को बढ़ाने की कोशिश में बल्लेबाजी करने उतरे। इस दौरान तेज गेंदबाज टॉम बेली ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी। ग्लूस्टरशायर के खिलाफ बल्लेबाजी के दौरान उनकी जेब से मोबाइल फोन गिर गया, जो न केवल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बल्कि विवाद का विषय भी बन गया।

अपनी पारी के शुरू में ही, बेली ने नॉन-स्ट्राइकर एंड पर

दो रन के लिए तेजी से टर्न लेने की कोशिश की, लेकिन शायद उन्हें एहसास नहीं हुआ कि उनकी जेब में उनका फोन है, जिससे उनका फोन फिसलकर पिच पर गिर गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

इसके बाद सवाल उठता है कि क्या मैदान पर मोबाइल ले जाना क्रिकेट के नियमों का उल्लंघन है? आखिर इस घटना ने खेल की निष्पक्षता को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

एमसीसी के नियमों के अनुसार मैच के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल खिलाड़ियों और अंपायरों दोनों के लिए प्रतिबंधित है। ये नियम मैच की निर्धारित शुरुआत के बाद से लागू होता है और खेल के मैदान पर इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

इस नियम खेल की निष्पक्षता को बनाए रखने और किसी भी संभावित अवैध संचार, जैसे सट्टेबाजी या मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए है। ऐसे में बेली का मैदान पर मोबाइल फोन ले जाना तकनीकी रूप से नियमों का उल्लंघन हो सकता है। हालांकि, ये स्पष्ट नहीं है कि इस मामले में कोई औपचारिक कार्रवाई हुई है या नहीं। ये भी नहीं पता कि अंपायर ने फोन वापस किया है या नहीं।

तापमान में आई गिरावट, तीन दिन ऐसा ही रहेगा मौसम

ओले और बिजली गिरने की संभावना, रिमझिम बारिश हुई

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा में सोमवार शाम हल्की बूंदा बांदी हुई, जिसके बाद से बादल छाए हुए हैं। सुबह से बादलों की लुका-छिपी का खेल जारी रहा। हालांकि दोपहर 12 बजे के बाद तेज धूप भी देखने को मिली। जहां तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक नोट किया गया, लेकिन शाम होते ही एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया।

रीवा में पिछले दो दिनों में तेज आंधी और हवा का प्रभाव भी देखने को मिला है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक रीवा में सोमवार को दिन का न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

हवा की गति 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। वहीं मंगलवार यानी 6 मई को जिले में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। जिले में कहीं कहीं बिजली गिरने, झंझावात और ओला वृष्टि की भी सम्भावना है। जबकि अगले तीन दिनों तक अब मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने वाला है। तापमान में मामूली वृद्धि की संभावना है।

तेज हवाओं और बवंडर के कारण विंध्य क्षेत्र में चार ट्रांसमिशन टॉवर क्षतिग्रस्त

ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है गत दिवस तेज हवाओं और बवंडर के कारण विंध्य क्षेत्र स्थित मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की 220 के.व्ही. अमरकंटक-सीधी तथा 220 के.व्ही. सीधी-रीवा ट्रांसमिशन सर्किट के चार टॉवर क्षतिग्रस्त हो गये। इस कारण अमरकंटक से सीधी 220 के.व्ही. सर्किट में विद्युत प्रवाह प्रभावित हुआ, लेकिन 220 के व्ही सबस्टेशन सीधी में वैकल्पिक ट्रांसमिशन सप्लाई उपलब्ध होने से क्षेत्र में इस कारण कोई विद्युत व्यवधान नहीं हुआ। साथ ही इससे अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन चचाई में उत्पादित विद्युत की निकासी एवं पारेषण पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा और अन्य सर्किट अनूपपुर एवं जबलपुर में विद्युत आपूर्ति निर्विघ्न बनी रही।72 मीटर ऊँचा टावर भी हुआ क्षतिग्रस्त - एम पी ट्रांसको के मुख्य अभियंता श्री संदीप गायकवाड़ ने बताया कि विंध्य क्षेत्र में सोन नदी के आसपास मौसम के अचानक बिगड़ने से उपरोक्त दोनों सर्किट में दो टॉवर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए तथा दो अन्य टॉवर आंशिक रूप से प्रभावित हुए। इन टॉवरों में से एक 72 मीटर ऊँचाई का विशेष ट्रांसमिशन टॉवर है, जो सोन नदी क्रॉसिंग के लिए स्थापित किया गया था। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद, क्षतिग्रस्त टॉवरों की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दिया गया है। प्रभावित सर्किटों से विद्युत आपूर्ति पुनः बहाल करने में कम से कम तीन सप्ताह का समय लग सकता है।

सतना में बसपा नेता की पीट-पीटकर हत्या

15 हमलावर लाठी-डंडों के साथ दिखे, पत्थर मारे, दो दिन पहले छोड़ी थी कांग्रेस

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। सतना में एक बसपा नेता की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। करीब 15 अज्ञात बदमाश शुभम साहू (26) पर लाठी-डंडे लेकर टूट पड़े। बदमाशों ने उसे पत्थर भी मारे। प्रारंभिक जांच में जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। शुभम ने दो दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली थी।

घटना रविवार रात 12.30 बजे महदेवा मोहल्ले की है। घायल शुभम को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से रीवा रेफर कर दिया गया। रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है।

मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया हैं, जिसमें 14-15 लोग लाठी-डंडे लिए हुए दिख रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों पंकज गौतम, रजनीश गौतम एवं विपिन गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी एक ही परिवार के है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

शुभम पहले यूथ कांग्रेस के महामंत्री और एनएसयूआई में सचिव रह चुके थे। हाल ही में वह बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए थे और भोपाल से सतना लौटे थे। बताया जा रहा है कि शुभम का अपने ही मोहल्ले के कुछ लोगों से जमीन विवाद चल रहा था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

शुभम साहू के खिलाफ शहर के सिविल लाइन, सिटी कोतवाली एवं कोलगवां थाने में 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें मारपीट, जमीनी विवाद जैसे मामले हैं। जांच में सामने आया है कि शुभम और उसके पिता महेश साहू यहां की कुछ निजी जमीनों पर कब्जा किए हुए है। एक गौतम परिवार है, जिसकी जमीन पर इनका जबरन कब्जा है। एक सिंह परिवार भी है। कई लोग शुभम साहू और उसके परिजनों की करतूत से परेशान थे। 2024 में शुभम पर जिलाबदर की कार्रवाई भी हो चुकी हैं।

पिता बोले- निगम अध्यक्ष ने रची साजिश: बीएसपी नेता शुभम के पिता महेश साहू ने नगर निगम अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी और उनके भाई उमेश चतुर्वेदी पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने बेटे के अंतिम संस्कार नहीं करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हत्या करने वाले निगम अध्यक्ष के बुआ के लड़के दिनेश गौतम को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। इसके अलावा वीडियो में दिख रहे अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किए जाए।

कलेक्टर ने विद्युत लाइन निर्माण की अनुमति का जारी किया आदेश

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड सतना, रीवा, सीधी विद्युत लाइन निर्माण की अनुमति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस लाइन में रीवा जिले के हुजूर तहसील के अन्तर्गत ग्राम सिलपरा एवं मगुरहाई के आसपास निर्माण कार्य प्रस्तावित है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने भारतीय तार अधिनियम 1985 की धारा 16 (1) तथा विद्युत आपूर्ति अधिनियम 2003 की धारा 164 के तहत अनुमति प्रदान की है। अब मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड बिना किसी बाधा के निर्माण कार्य कर सकती है। अनुमति मिलने के बाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत कंपनी को प्रस्तावित निर्माण स्थलों में जनहित से जुड़े तथा उनकी अधिकारिता की सीमा में किए जाने वाले किसी भी निर्माण कार्य में कोई विरोध, अवरोध अथवा व्यवधान नहीं डालेगा। ऐसा करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान परिस्थितियों में विद्युत लाइन के विस्तार के निर्माण के लिए भूमि के उपयोग की अनुमति की व्यक्तिगत रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है तथा इसके संबंध में व्यक्तिगत रूप से सुनवाई किया जाना व्यावहारिक नहीं है। इसलिए यह आदेश एक पक्षीय रूप में जारी किया जाता है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक तथा एसडीएम हुजूर को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने एवं निर्माण कार्यों में बाधा डालने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

रीवा में 26 आउटसोर्स कर्मचारी निकाले, विरोध प्रदर्शन का पांचवा दिन

अमरण अनशन पर बैठे तीन लोगों की तबीयत बिगड़ी

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा में आउटसोर्स कर्मचारी बहाल की मांग को लेकर रीवा में 5 दिनों से अमरण अनशन जारी है। तीन प्रदर्शनकारियों गौरव तिवारी, मनोज वर्मा और प्रमोद चतुर्वेदी की तबीयत बिगड़ गई है, जिन्हें डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी है। इसके बावजूद वो अनशन पर अड़े हुए हैं।

बिजली विभाग में मीटर रीडर के पद पर पदस्थ 26 लोगों को निकाल दिया गया था।

लोगों का कहना है कि इससे पहले भी इन कर्मचारियों ने धरना दिया था। तब मुख्य अभियंता ने 15 दिन का समय लेकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसी कारण अब फिर से आंदोलन की राह चुनी गई है।

तीन दिन में बहाली और सेमी स्किल्ड दर्जा: अनशन पर बैठे कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि सभी 26 आउटसोर्स कर्मचारियों को तीन दिन के भीतर बहाल किया जाए। उन्हें सेमी स्किल्ड श्रेणी में ही रखा जाए। इसके अलावा जुलाई 2024 में कनिष्ठ अभियंता द्वारा तैयार किए गए लेटर के आधार पर ही काम दिया जाए।

भ्रष्टाचार का आरोप, मजबूरी में आमरण अनशन: अगस्त क्रांति मंच के कुंजबिहारी तिवारी ने कहा कि आउटसोर्सिंग में काम कर रहे ये मीटर रीडर्स पहले 2000 रुपए में काम कर रहे थे। जब सरकार ने न्यूनतम वेतन 12,230 रुपए + पीएफ + ईएसआईसी देना शुरू किया तो कुछ अधिकारियों ने भ्रष्टाचार कर 50 से 80 हजार रुपए में बाहर के लोगों को भर्ती कर लिया और पुराने कर्मचारियों को निकाल दिया।

उन्होंने कहा कि हम 10 महीने से जबलपुर से लेकर रीवा तक भटकते रहे। अब जब सरकार सुनवाई नहीं कर रही तो आमरण अनशन ही विकल्प बचा है। मुख्य अभियंता का कहना है कि विभागीय निर्णय नियमों और न्यायिक प्रक्रिया के तहत लिए जाते हैं। पूरी पारदर्शिता रखी जाती है। अनशन अगस्त क्रांति मंच फाउंडेशन के नेतृत्व में आयुक्त कार्यालय के सामने चल रहा है।

मुसीबत में साथ आए लोग, शादी की तैयारी की पूरी

सतना में घर में आग लगने से जल गया था दहेज

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। सतना के चित्रकूट क्षेत्र के सेजवार गांव में माहेश्वरी यादव के घर में बेटी की शादी की रस्में मांगलिक गीतों के साथ शुरू हो गई हैं। 2 मई की रात को हुई आगजनी में माहेश्वरी यादव और उनके भाई की पूरी गृहस्थी जलकर राख हो गई थी। बेटी की शादी का सामान भी इस हादसे में नष्ट हो गया था। लेकिन इस मुश्किल समय में पूरा गांव और क्षेत्र के लोग परिवार की मदद के लिए आगे आए।

ग्रामीणों ने अपनी क्षमता के अनुसार मदद की। कोई 100 रुपए लेकर आया तो कोई 10,000 रुपये। कुछ लोगों ने कपड़े दिए तो कुछ ने बर्तन। आशुतोष द्विवेदी सेवा संस्थान ने अनाज और परिवार के लिए कपड़ों के साथ बेटी के साथ जाने वाले उपहारों की व्यवस्था की। पूर्व विधायक नीलांशु चतुर्वेदी, समाजसेवी विक्रम पटेल और मुकेश पटेल ने भी सहयोग किया।कुछ लोग मंडप सजाने में जुटे हैं तो कुछ बारातियों के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। सोमवार की शाम को बारात आई और शादी संपन्न हुई।

मऊगंज में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना संबंधी बैठक आज

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)।. मऊगंज में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना संबंधी बैठक अब 6 मई को दोपहर एक बजे से कलेक्ट्रेट कार्यालय में मऊगंज में आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर मऊगंज संजय कुमार जैन करेंगे। बैठक में आदर्श ग्राम योजना के तहत वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 में संबंधित ग्राम पंचायतों को आवंटित राशि के उपयोग तथा निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। जिला संयोजक आदिमजाति कल्याण विभाग कमलेश्वर सिंह ने संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है। बैठक में संबंधित गांवों के सरपंच तथा ग्राम पंचायत सचिव भी उपस्थित रहेंगे।

विहिप पदाधिकारी ने किया एग्जाम के नियम का विरोध, स्टूडेंट की बहन भी नाराज

नीट परीक्षा में जनेऊ उतरवाना सनातन संस्कृति के खिलाफ

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा में रविवार को हुई नीट परीक्षा में टीआरएस कॉलेज में बनाए परीक्षा केंद्र पर बच्चे का जनेऊ उतरवाया गया। हिंदू संगठन के पदाधिकारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसका विरोध किया। छात्र की बहन ने भी वीडियो जारी कर जनेऊ उतरवाने को गलत ठहराया। उसने इसे सनातन संस्कृति के विरूद्ध बताया।

विश्व हिंदू परिषद के जिला सह संयोजक बालकृष्ण द्विवेदी ने लिखा कि टीआरएस कॉलेज में नीट परीक्षा मे परीक्षार्थियों को प्रवेश देने में बच्चो का जनेऊ उतार लिया गया, यह सनातन परंपरा का घनघोर अपमान किया गया ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। लड़की ने परीक्षा केंद्र पर भाई का जनेऊ उतरवाने की बात पर नाराजगी जताई। उसने भी इसे सनातन संस्कृति का अपमान होना बताया। इसका वीडियो सामने आया है।

Pandit Balkrishna D... is with Vivek Mishra and 8 others.
14h ·

TRS कॉलेज में NEET परीक्षा मे परीक्षार्थियों को प्रवेश देने में बच्चो का जनेऊ उतार लिया गया , यह सनातन परंपरा का घनघोर अपमान किया गया ऐसा करने बालो पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए #neet2025 #janeu
Madhya Pradesh Police Collector Rewa SP Rewa MP CM Madhya Pradesh Dr Mohan Yadav National Commission for Protection of Child Rights

जानकारी के अनुसार रविवार को रीवा के 13 परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी परीक्षा हुई। जहां हर सेंटर में 500 के करीब परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। कड़ी सुरक्षा के बीच नियमों का भी कड़ाई से पालन कराया गया।

इस मामले में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा नीट एग्जाम के लिए जो भी रूल और रेगुलेशन तय की जाती है, उसका पालन कराया गया है। जहां ऊंची हील वाली सैंडल, ब्रेसलेट, स्मार्ट वॉच, लंबी आस्तीन की शर्ट या अन्य संदेहास्पद चीजें प्रतिबंधित की गई थी।

जूते तक पहनने की अनुमति नहीं

नीट यूजी परीक्षा में परीक्षार्थी पारदर्शी बोतल में पानी लेकर पहुंचे। परीक्षा केन्द्र में जूते पहनने की अनुमति नहीं दी गई। जहां परीक्षार्थी कम हील की सैण्डल या चप्पल पहनकर पेपर देने पहुंचे। परीक्षा केन्द्र में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, इयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हीट बैण्ड आदि ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहा।

चश्मा, घड़ी, बेल्ट, कैप, हैण्ड बैग, कैमरा, ब्रेसलेट और किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ का ले जाना भी प्रतिबंधित रहा। अपारदर्शी बोतल में पानी ले जाने की अनुमति नहीं थी।

वहीं नकल से बचने के लिए परीक्षार्थियों के कपड़ों का भी खासा ख्याल रखा गया। परीक्षार्थी हल्के कपड़े पहन परीक्षा देने पहुंचे, जिनकी आस्तीन लंबी न हो। फैंसी पाकेट, जिपर, बैज आदि लगे कपड़े पहनकर परीक्षा केंद्र में जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहा। परीक्षा केंद्र में परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित निर्देशों का पूरी तरह से पालन कराया गया।

सतना में पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार

लंबे समय से चल रहा था घरेलू विवाद

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। सतना जिले के नागौद थाना क्षेत्र के पीली कोठी मोहल्ले में सोमवार को 68 वर्षीय व्यक्ति ने घरेलू विवाद के बाद अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के समय दोनों घर में अकेले थे। बेटे ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस के अनुसार, आरोपी मंगल प्रसाद (68) और उनकी पत्नी माया देवी (65) के बीच काफी समय से आपसी तनाव था। सोमवार को किसी बात को लेकर फिर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। गुस्से में आकर मंगल प्रसाद ने पत्नी का गला दबा दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही दंपती का बेटा तुरंत मौके पर पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। नागौद पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया।

थाना प्रभारी अशोक पांडेय ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला घरेलू विवाद का प्रतीत होता है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और अन्य पहलुओं की भी गहनता से जांच की जा रही है।

कृषि के विकास के लिए समन्वित प्रयास करें - कमिश्नर जामोद

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा संभाग में कृषि तथा उससे जुड़े विभागों की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सभी जिलों में कृषि और उससे जुड़े विभागों की समन्वय बैठकें आयोजित की जा रही हैं। गत दिवस मैहर में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का आधार खेती है।

किसान केवल परंपरागत तरीके से अनाजों की खेती करके अधिक लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है। किसानों को खेती की आधुनिक तकनीक के साथ-साथ उद्यानिकी, मछलीपालन, पशुपालन, मुर्गीपालन जैसे अन्य कार्यों से जोड़ना आवश्यक है। तभी उसकी आय दुगनी होगी और खेती लाभ का धंधा बनेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि, उद्यानिकी तथा पशुपालन विभाग के जिला, विकासखण्ड और मैदानी कर्मचारी समन्वित प्रयास करें। एक-दूसरे के विभाग की योजनाओं की पूरी जानकारी रखकर योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करें। इन सभी विभागों का मुख्य लक्ष्य किसान के जीवन को बेहतर बनाना है। समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। सभी अधिकारी एक-दूसरे से सतत संपर्क और संवाद रखें।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में संयुक्त संचालक कृषि जेएस नेताम ने बैठक के उद्देश्यों और कृषि विभाग की प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में कमिश्नर ने कृषि विभाग की आत्मा परियोजना द्वारा तैयार सफलता की कहानियों की पुस्तिका का विमोचन किया। कमिश्नर ने बैठक में तीन किसानों को सोलर उपकरण का वितरण किया।

बैठक में कलेक्टर मैहर श्रीमती रानी बाटड, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत संजना जैन, उप संचालक कृषि मनोज कश्यप, उप संचालक उद्यानिकी अनिल सिंह, उप संचालक पशुपालन डॉ पीके द्विवेदी, उप संचालक मछली पालन डॉ अंजना सिंह, उप पंजीयक विजय मिश्रा, संभागीय कृषि यंत्री एसके नरवरे, सहायक संचालक कृषि प्रीति द्विवेदी तथा जिला एवं विकासखण्ड स्तर के कृषि से जुड़े विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक/प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा मीडिया ऑडीटर पब्लिकेशन प्रा.लिमि. राजीव मार्ग निराला नगर रीवा से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय राजीव मार्ग निराला नगर रीवा से प्रकाशित, **संपादक संदीप द्विवेदी**, आर.एन.आई नं. 69082/97, डाक पंजीयन क्र.- म. प्र./ रीवा संभाग/ 46/2023-2025, प्रधान कार्यालय रीवा (सिटी कार्यालय चक्रधर सिटी सेंटर रीवा) फोन. नं. 9589645803, 7974467831 Mediaauditor1@gmail.com सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रीवा होगा।